20 सितम्बर, 2024 ★ वर्ष 33, पृष्ठ संख्या 68, अंक 9

राजस्थान सुजस

RISING
RAJASTHAN

REPLETE • RESPONSIBLE • READY

एक लक्ष्य, एक आह्वान
राइजिंग राजस्थान

RISING
RAJASTHAN
9-10-11 DEC 2024 • JAIPUR

राज्य सरकार के
300 दिवस
विशेषांक

धरा तर–बतर
बांधों से खुशखबर

दीर्घायु की प्रार्थना, आरोग्य का आह्वान
गोविन्द के दरबार में, तुलसी का दान।।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्री गोविन्ददेवजी महाराज के दर्शन कर प्रभु से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ व सुयशपूर्ण जीवन की प्रार्थना की। उन्होंने इस उपलक्ष्य में तुलसी वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर श्रद्धालुओं को तुलसी के पौधे वितरित कर सभी से पर्यावरण संरक्षण हेतु योगदान देने का आग्रह किया।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 33 अंक 09
सितम्बर, 2024

इस अंक में

'अहं' से 'वयं' तक राजस्थान 05

अग्रणी राजस्थान को समर्पित 300 दिन 50

आस्था	2
संपादकीय	4
पेपर लीक के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई	10
युवा उम्मीदों को पंख...	12
संबल और सम्मान, खुशहाल किसान	15
आत्मनिर्भरता की राह पर शक्ति स्वरूपा	18
ऊर्जा में सिरमौर, सरप्लस की ओर	20
हर घट जल की 'हठ' पूरी	23
पहला सुख – उत्तम स्वास्थ्य, सुलभ उपचार	26
फील्ड पर नजर	30
यूएई और कतर में अन्तरराष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो	46
निवेशकों की हरसंभव मदद करेगी राज्य सरकार	48
राजस्थान में उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं	49
सब जन – स्वजन	66

भक्ति की भावना 28

रुख स्पष्ट है .. 7 करोड़ रुख प्रत्यक्ष हैं 64

राइजिंग राजस्थान 31

तरंग शक्ति–2024 67

प्रधान संपादक
सुनील शर्मा

संपादक
अलका सक्सेना

सह-संपादक
डॉ. रजनीश शर्मा

सहायक संपादक
मोहित जैन

संपादकीय सहयोग
चंद्रशेखर पारीक

आवरण छाया
सुजस

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
रेनबो ऑफसेट प्रिंटर्स
लागत मूल्य 44.00 रुपये

संपर्क
संपादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. 80948-98098
e-mail
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website
www.dipr.rajasthan.gov.in

संपादकीय

साफ होने लगी तस्वीर ...

आने वाले कुछ महीने और वर्ष में प्रदेश की तकदीर और तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। कुछ ही दिन पहले आए बजट ने प्रदेश के आने वाले सुनहरे दिनों की जो झलक दिखाई थी, वह अब लगातार साफ होती जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणाओं को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने की कोशिश और बजट के बाद भी हर वर्ग के लिए एक के बाद एक लिए जा रहे लोकल्याणकारी निर्णय, नवाचार और उन्हें लागू करने के रोडमैप की सुदृश्यता इसका कारण है।

इन नवाचारों में सबसे बड़ा नवाचार जयपुर में दिसम्बर में होने वाले 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024' के रूप में हमारे सामने है। मुम्बई में पहली इन्वेस्टर मीट से प्रारम्भ होकर मुख्यमंत्री महोदय की सफल कोरिया-जापान की अन्तरराष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट ने प्रदेश की इस 'सिनर्जी' को प्रदेश और देश की सीमाओं से परे विदेशों तक पहुंचा दिया है। मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हुए इन दौरों से विदेशों में रह रहे राजस्थानियों द्वारा भी अपनी मिट्टी से गहरा जुड़ाव अनुभव किया जा रहा है। इस समिट को पूरे प्रदेश के लिए 'गेम चेंजर' कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। मुम्बई के पहले इन्वेस्टर मीट में ही 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश एमओयू उम्मीद जगाने वाले हैं, जो अगले पांच वर्ष में प्रदेश को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।

बीते करीब 300 दिवस के दौरान राज्य सरकार के लोकल्याणकारी फैसलों से पूरे राज्य में उत्साह का जो माहौल बना है उसमें बिजली, पानी, सड़क निर्माण जैसे आधारभूत ढांचे से जुड़े सेक्टर, चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, कृषि, बेहतर कानून-व्यवस्था, रोजगार जैसे मानव संसाधन और युवा, महिला, किसान, श्रमिक, छात्रों सहित विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों की बड़ी भूमिका है। प्रदेश में अच्छे मानसून और पानी से लबालब भरे बांधों ने इस उत्साह को और ऊंचाई दी है। 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024' की सफलता के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और भविष्य के निवेश की संभावनाओं के साथ ही राज्य सरकार द्वारा पिछले 9 माह में किए गए फैसलों की झलक देता सितम्बर माह का यह अंक आप सुधि पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

(सुनील शर्मा)
प्रधान सम्पादक

'अहं' से 'वयं' तक राजस्थान

विवेक जादौन
उप निदेशक

नई सुबह, नया उजास

12 दिसम्बर, 2023 का दिन। राजस्थान विधानसभा चुनाव का परिणाम आए नौ दिन बीत चुके थे। बहुमत प्राप्त दल के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक में प्रदेश की जनता को आज अपना नया मुख्यमंत्री मिलने वाला था। संभावना व्यक्त की जा रही थी कि मुख्यमंत्री के तौर पर कोई चौंकाने वाला नाम आ सकता है। इस बीच मंच पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के नजदीक बैठीं पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे नाम प्रस्तावित करती हैं- "श्री भजनलाल शर्मा"। मंच के सामने बैठे विधायकगण अगल-बगल देखकर उस चेहरे को ढूंढने लगते हैं। और सबकी नजर जाकर टिकती है, सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे पहली बार के विधायक श्री भजनलाल शर्मा पर। वरिष्ठ नेता एवं नव निर्वाचित विधायक श्री किरोड़ीलाल मीणा, श्री मदन दिलावर, श्री झाबर सिंह खर्रा और अन्य सभी विधायक उनके नाम का समर्थन करते हैं। सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद चेहरे पर तैरते आश्चर्य और विनम्रता के मिश्रित भावों के साथ श्री भजनलाल शर्मा हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हैं। क्या यह एक नई सुबह है, नई शुरुआत है !!

आठ करोड़ प्रदेशवासियों के मन में कौंध रहे इस सवाल का जवाब 15 दिसम्बर, 2023 को उस वक्त मिल गया, जब शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू किए। उसी रात, पहली बार मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश अब निराशा के भंवर को पीछे छोड़ते हुए डबल इंजन सरकार के साथ नई उम्मीदों के सफर पर निकलने वाला है। अपने मजबूत इरादों की झलक देते हुए उन्होंने महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार उन्मूलन, बेहतर कानून-व्यवस्था सहित सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं गिनाईं। उन्होंने पेपरलीक अपराधियों को सख्त सजा दिलवाने के लिए एसआईटी गठित करने और संगठित अपराध का खात्मा कर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र में जितनी भी घोषणाएं की हैं, सभी को पूरा करेंगे। उनका संदेश साफ था कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में चलते हुए प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों, गरीबों, महिलाओं एवं युवाओं को ध्यान में रखते हुए मजबूत फैसले लेगी एवं राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएगी। पहली बार के मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन जनता की नब्ज भांप ली थी।

कार्य संस्कृति में आमूल-चूल बदलाव

इसके बाद, तकरीबन हर दिन ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जनता के हितों से जुड़े, हर मामले की फाइलें तलब करनी शुरू कीं। दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाते हुए बड़े अधिकारियों से लेकर सामान्य कर्मचारियों तक को ये संदेश दिया गया कि भ्रष्टों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और कर्तव्यनिष्ठ कार्मिकों को छेड़ा नहीं जाएगा। राजधानी जयपुर ही नहीं, गांव-कस्बों में भी सरकारी दफ्तर समय पर खुलने लगे और अफसर-कर्मचारी समय पर पहुंचने लगे। मुख्यमंत्री आवास से लेकर मंत्रियों, उच्चाधिकारियों के दफ्तरों और सभी सरकारी कार्यालयों पर नियमित जनसुनवाई का आयोजन किया जाने लगा। खुद मुख्यमंत्री का काफिला वक्त-जरूरत ट्रैफिक सिगनल पर रुकने लगा। जनता के हाल जानने के लिए नए सीएम कभी ट्रेन में सफर करते तो कभी बाजारों में चाय के बहाने या पार्क में मॉर्निंग वॉक के बहाने जाकर आमजन के मन की बात जानने लगे। जिलों के प्रभारी मंत्री और आला अधिकारी भी अब जिलों में कैम्प कर झुलसाती गर्मी और भारी बारिश के हालात का जायजा लेकर माकूल व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते। कार्य संस्कृति में आमूल-चूल बदलाव की आहट सबको समझ आने लगी और यह भी मालूम चलने लगा कि इस सरकार में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वह है "पीपुल फर्स्ट" की नीति।

अन्त्योदय की ओर

जनहित के मामलों पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच बेमिसाल है। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिये हैं, जिनसे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना में 450 रुपये में गैस सिलेण्डर, पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में कमी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दर बढ़ाने, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारम्भ कर पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी, गेहूं के समर्थन मूल्य पर बोनस देने, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए लेवल-1 में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत करने, पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण सीमा 33 प्रतिशत करने जैसे संकल्प पत्र के कितने ही वादे पूरे किए जा चुके हैं। युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार अवसरों का सृजन किया जा रहा है। सरकारी नौकरी हासिल करने वाले युवाओं की हौसला अफजाई के लिए मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित कर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं।

2 अक्तूबर, 1977 को गांधी जयंती पर तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. भैरोंसिंह शेखावत ने जिस 'अन्त्योदय' कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, वह निर्धनों में भी निर्धनतम की पहचान और उत्थान का संभवतः सर्वप्रथम सफल प्रयास था। राजस्थान में अन्त्योदय उपलब्धि के बारे में श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि यह सम्पूर्ण क्रांति का दूसरा चरण है। अन्त्योदय के लिए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को यदि सम्पूर्ण क्रांति का अगला चरण कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

धरती और धरती पुत्रों की सरकार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब कहते हैं कि यह धरती और धरती पुत्रों की सरकार है, तो यह बात सिर्फ कहने भर के लिए नहीं होती। गांव और गरीब के यथार्थ को उन्होंने करीब से देखा है। बड़ी मुद्दत बाद राजस्थान को ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, जो स्वयं खेती-बाड़ी से जुड़े रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद राजस्थान विधानसभा में किसान की तकलीफों की बात करते हुए उन्होंने कहा था, "किसान की हकीकत वह जानता है, जिसके पैर में बिवाई फटती है, जिसने गरीबी देखी हो, जिसने गरीब का सहयोग किया हो। मैंने मेरे जीवन में हल चलाया है, बैल का।... मालगाड़ी में बैठकर नागौर में परबतसर के मेले में बैल लेने गया हूं।" कोई हैरत नहीं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो शुरुआती बड़े फैसले किए, किसान उन निर्णयों के केन्द्र में था। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना (एकीकृत ईआरसीपी) और ताजेवाला हैड से यमुना जल के समझौते का क्रियान्वयन होने से राजस्थान के करीब आधे जिलों की सिंचाई की जरूरत पूरी होगी। हजारों मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ाने के पीछे मुख्यमंत्री का बड़ा संकल्प यह है कि किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली मिल सके।

ईश्वरीय शक्ति में अनन्य आस्था

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एक कुशल संगठक, दूरदर्शी राजनेता तो हैं ही, उनका एक और रूप भी है। ईश्वर और धर्म में उनकी अनन्य आस्था है। वे अक्सर कहते भी हैं, "बंसी वाले का मुझ पर आशीर्वाद है और जो कुछ अच्छा होता है, वह भगवान की कृपा से ही संभव है।" अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय मिलते ही वे पूंछरी का लौठा में भगवान श्रीनाथजी के दर्शन करने जाते हैं। हाल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर जब वे पूंछरी का लौठा (डीग) और उज्जैन में सांदीपनि आश्रम गए तो उन्होंने श्रीकृष्ण गगन पथ विकसित करने की घोषणा भी की। सरकार बनने के कुछ माह बाद ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा अपनी मंत्रिपरिषद और विधायकों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने गए थे। श्रीराम के नव्य-भव्य मंदिर के बाहर मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक एक साथ बैठ कर पूरे श्रद्धा भाव के साथ जय श्रीराम का उद्घोष और सस्वर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। जनमानस की स्मृति में यह दुर्लभ दृश्य अविस्मरणीय पल के रूप में लम्बे समय तक दर्ज रहेगा। सभी श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें, इसके लिए मुख्यमंत्री की पहल पर राजस्थान से अयोध्या के लिए बस और हवाई सेवा शुरू की गई है। राज्य सरकार इस साल करीब 36 हजार वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या सहित अन्य तीर्थों की यात्रा भी करवा रही है।

जनअपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरने की ललक

राज्य सरकार क्षेत्रीय जरूरतों व जनअपेक्षाओं के मुताबिक काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्रीय पीएसयू कम्पनियों के साथ एमओयू कर ज्वाइंट वेंचर बनाए जा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर मंजूरी दी जा रही है। अक्षय ऊर्जा में तो आज राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। इसका श्रेय कम समय में ही सरकार द्वारा अपनाई गई अनुकूल निवेश नीतियों और सुधारों को जाता है। आने वाले समय में सरकार राजस्थान में इंटरसिटी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाने जा रही है। प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं के विकास के लिए केन्द्र सरकार के साथ संयुक्त उद्यम बनाने का निर्णय किया गया है। शहरों में ट्रैफिक जाम को रोकने के लिये ओवरब्रिज, एलिवेटेड रोड बनवाने की परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। वर्षों से लटकी पीकेसी-ईआरसीपी और यमुना जल समझौते को क्रियान्वित करने का काम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने किया है।

RISING RAJASTHAN
9-10-11 DEC 2024 • JAIPUR
REPLETE • RESPONSIBLE • READY

विजन और इनोवेशन वाली सरकार

कहा जाता है कि आंखें तो सबके पास होती हैं, लेकिन दृष्टि सबके पास नहीं होती। दृष्टि यानी विजन जिसके पास होता है, वही कुछ बड़ा करने का साहस जुटा पाता है। नई सरकार दूरदर्शी सोच के साथ ऐसे ही हिम्मत वाले काम कर रही है। देश-दुनिया के सभी बड़े औद्योगिक घरानों तथा संस्थानों को तेजी से पनप रहे अन्य विकसित राज्यों की टक्कर में सुविधाएं देकर बुलाने का काम राज्य सरकार कर रही है। अमूमन निवेशक सम्मेलनों का आयोजन राज्य सरकारों द्वारा कार्यकाल के चौथे या पांचवें वर्ष में किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार अपने कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने से ठीक पहले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है। सोच स्पष्ट है कि जो निवेश प्रस्ताव आएं वे महज कागजों तक सीमित न रह जाएं। हर प्रस्ताव को धरातल पर उतारने का इरादा कर सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए देश-विदेश में रोड शो से लेकर जिला स्तर पर निवेशकों को लुभाने के लिए इन्वेस्टर मीट आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि "वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 'विकसित राजस्थान' का होना जरूरी है। इसके लिए हम अपने कार्यकाल के 5 वर्षों में ही राज्य को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।"

नॉन लीनियर अप्रोच ऑफ गवर्नेन्स

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार का काम करने का तरीका थोड़ा नहीं बल्कि काफी हटकर है। इसका एक वाकया मुंबई में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के रोड शो में मुख्यमंत्री ने खुद बताया। दरअसल, बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर निर्माता-निर्देशक के.सी. बोकाड़िया जयपुर में मुख्यमंत्री से मिलने आए। बोकाड़िया ने उनसे कहा कि वह एक फिल्मसिटी बनाना चाहते हैं और इसके लिए कई राज्यों में जा चुके हैं। मुख्यमंत्री के पूछने पर उन्होंने बताया कि जयपुर में फिल्मसिटी बनाने की उनकी इच्छा है। इस पर, मुख्यमंत्री ने दो अधिकारियों के साथ उन्हें जगह देखने भेज दिया। कुछ घंटे बाद वह दोबारा आए तो मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या उन्होंने जमीन देख ली है? श्री बोकाड़िया ने बताया कि उन्होंने चार जगहों पर जमीन देखी है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उसी दिन उस जमीन को फाइनल कर दिया और उनसे कहा, "आइए राजस्थान में फिल्मसिटी बनाइए।"

आम तौर पर सरकारें एक-रेखीय पद्धति यानी लीनियर अप्रोच पर काम करती हैं, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में लम्बा समय लगता है। लेकिन, वर्तमान राज्य सरकार नॉन-लीनियर अप्रोच अपनाने में यकीन रखती है यानी किसी भी निर्णय या समाधान पर पहुंचने के लिए एक साथ कई स्तरों पर कार्य करते हुए उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाता है। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत का कथन भी इसकी तस्दीक करता है, "राजस्थान सरकार महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय कुछ ही घंटों में ले लेती है। राजस्थान सरकार की समन्वित निर्णय लेने की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय कुछ घंटों के भीतर लिए जाएं। कुछ महीने पहले विभागों के सचिवों का औसत फाइल निपटान समय लगभग 30 घंटे था और अब यह घटकर औसतन केवल 4 घंटे रह गया है।"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 'विकसित भारत' के संकल्प को नारी, युवा, किसान और गरीब के चार 'अमृत स्तंभों' पर टिका बताते हैं। यही चार उनके लिए सबसे बड़ी जातियां हैं, जिनका उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। ये चारों जातियां जब सारी समस्याओं से मुक्त होंगी और सशक्त होंगी तो स्वाभाविक रूप से पूरा देश सशक्त होगा। प्रखर विचारक पं. दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद ही इसका मूल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने इन्हीं पदचिन्हों पर चलते हुए राजस्थान को "अहं" से "वयं" तक ले जाने की यात्रा प्रारम्भ की है। उन्नत, खुशहाल और विकसित राजस्थान की नींव रखी जा रही है। आप भी हाथ बढ़ाकर इसमें भागीदार बनिए। ■

भर्ती परीक्षाओं में शुचिता की पुनर्स्थापना

दूर होने लगी अभ्यर्थियों की चिंता

प्रदेश में अभ्यर्थियों के लिए एक दु:स्वप्न की तरह भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का काला अध्याय अब बीते कल की बात होता जा रहा है और भर्ती परीक्षाओं में खोया उनका विश्वास पुन: लौट आया है। शपथ लेने के दूसरे ही दिन 16 दिसम्बर 2023 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक प्रकरणों की रोकथाम एवं इस सम्बन्ध में दर्ज मामलों में त्वरित जांच एवं दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए राज्य स्तर पर **एसआईटी** का गठन कर इस विषय पर उनकी गंभीरता और प्राथमिकताओं को रेखांकित कर दिया था ...

राज्य में विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक के इतिहास को देखते हुए गठित की गई एसआईटी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य कर रही है।

व्यवस्था की जड़ें खोदने वाले लोगों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्रवाई न्याय के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। पेपरलीक के प्रकरणों में कई अपराधी, गैंग के सरगना सम्मिलित थे। उनकी गिरफ्तारी ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून के साथ खिलवाड़ का प्रयास किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की निर्णायक कार्रवाइयों ने न केवल आसन्न भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति संदेह को दूर किया है, बल्कि भ्रष्टाचार के सम्भावित प्रयासों पर भी प्रभावी लगाम कसी है।

जेईएन पेपर लीक, उप निरीक्षक पुलिस एवं प्लाटून कमान्डर भर्ती परीक्षा 2021, पेपर लीक में सम्मिलित मुख्य गैंग सरगनाओं के साथ-साथ उनके सहयोगी तथा गलत तरीके से लाभान्वित हुए परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है और वर्तमान में इनमें से अधिकांश सलाखों के पीछे हैं।

अपराधियों पर इस प्रकार के वज्र प्रहार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हुआ है। इन ठोस कार्रवाइयों ने कानून के साथ खिलवाड़ की मंशा रखने वाले सभी गलत तत्वों के मन में भय का संचार किया है। एसआईटी की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि निराश एवं हताश नवयुवकों में आशा का संचार करना है। गैंग के सदस्यों एवं अनुचित लाभार्थियों पर बिना भेदभाव एवं जिस कानूनी सख्ती के साथ कार्रवाई की गई है, इससे नवयुवकों में उम्मीद जगी है। अब तक 108 भर्ती परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित होने से अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों में सरकारी संस्थाओं के प्रति विश्वास जगा है।

एसआईटी ने हेल्पलाइन जारी कर प्राप्त सूचनाओं पर रात-दिन लग कर जिस तत्परता से कार्रवाई की, उससे आमजन में एक सजग प्रहरी होने का भाव पैदा किया है। इसके फलस्वरूप 8 माह में 3018 परिवाद प्राप्त हुए हैं। आमजन द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग कर चयनित लाभार्थियों के बारे में सटीक सूचना दी गई है एवं सूचना का प्रवाह अभी भी जारी है। 1632 परिवाद दर्ज कर जांच जारी है।

एसआईटी की उपलब्धियां

विभिन्न परीक्षाओं का सफल आयोजन

राजस्थान लोक सेवा आयोग की 01 जनवरी 2024 से 03 सितम्बर 2024 तक छोटी-बड़ी कुल 96 परीक्षाएं एवं राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की 12 बड़ी परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के आयोजित हुई हैं। इन

परीक्षाओं के सफल आयोजन में एसआईटी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनके अलावा केन्द्र सरकार की अनेक भर्ती परीक्षाएं तथा सरकारी विभागों द्वारा स्वयं के स्तर पर भी कई परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी परीक्षाएं सुचारू रूप से एवं बिना किसी गड़बड़ी के आयोजित की गईं।

सख्ती जारी

राज्य सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता लाने की नीति के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2013 में पर्चा लीक करने वाले आरोपी व्याख्याता को राजकीय सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई 24 सितम्बर, 2024 को राजकीय सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों पर रोक) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत की गई है।

अपराधियों के विरूद्ध ठोस कार्रवाई, एफआईआर

- एक जनवरी से 02 सितम्बर 2024 तक कुल 52 एफआईआर एसओजी थाने में दर्ज की गई हैं, जिसमें पेपर लीक, डमी अभ्यर्थियों के सहारे चयन तथा प्राईवेट विश्वविद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट थोक में जारी करने (जिनका इस्तेमाल बड़े स्तर पर सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने में किया गया है) से सम्बन्धित प्रकरण शामिल हैं।
- कनिष्ठ अभियन्ता भर्ती परीक्षा से सम्बन्धित पुलिस थाना सांगानेर, जयपुर पूर्व में दर्ज प्रकरण में पेपर लीक करने वाले गैंग के मुखिया एवं इनके प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है।
- कनिष्ठ अभियन्ता भर्ती परीक्षा के अनुसंधान से उप निरीक्षक पुलिस एवं प्लाटून कमान्डर भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक एवं परीक्षा के दौरान व्यापक गड़बड़ियों का खुलासा करते हुए पेपर लीक गैंग के मुखिया समेत गैंग के प्रमुख सदस्यों तथा प्रशिक्षणरत उप निरीक्षकगण को भी गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर इलाके के जगदीश बिश्नोई गैंग एवं बीकानेर के तुलसाराम कालेर-पोरव कालेर तथा इनसे सम्बन्धित कई छोटे-छोटे मोडयूल का खुलासा कर उनके सदस्यों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, जो अभी भी जेल में ही हैं।
- उप निरीक्षक पुलिस एवं प्लाटून कमान्डर भर्ती परीक्षा 2021 में गड़बड़ी करने के आरोप में 72 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है एवं अभी भी अनुसंधान तीव्र गति से जारी है। 42 उप निरीक्षक (38 प्रशिक्षणरत उप निरीक्षक व 4 उप निरीक्षक जिन्होंने ज्वाईन नहीं किया) गिरफ्तार किए गए हैं, जो अभी भी जेल में हैं।
- इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा 12 अगस्त 2024 को विस्तृत सुनवाई के उपरान्त उप निरीक्षक पुलिस एवं प्लाटून कमान्डर भर्ती परीक्षा 2021 में गिरफ्तारशुदा 11 ट्रेनी उपनिरीक्षक द्वारा लगाई गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।
- बेकरिया पेपरलीक प्रकरण, उदयपुर, दिसम्बर 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 के प्रकरण में गिरफ्तारशुदा 06 अपराधियों की जमानत याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ द्वारा सुनवाई के उपरान्त खारिज कर दी गई। इस प्रकरण के मुल्जिम वर्ष 2023 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं।

- राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठाकर अनुचित साधनों के प्रयोग से चयनित होने वालों की संख्या बहुत अधिक होने का खुलासा हुआ एवं विभिन्न परीक्षाओं में इसके निराकरण के उपाय करवाये गये, जिससे इस प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगा है। एसओजी में एवं राजस्थान के कई जिलों में इससे सम्बन्धित अलग-अलग प्रकरण दर्ज हुए हैं। पेपर लीक जैसी गम्भीर समस्या को एसआईटी ने उजागर कर परीक्षा प्रणाली में सुधार करवाए हैं।
- पेपर लीक करने वाले गैंग एवं डमी अभ्यर्थी की सहायता से चयन कराने वाले गैंग द्वारा बिना योग्यताधारी अभ्यर्थियों को अनुचित साधनों से चयन करवा दिया जाता था। जिसमें वास्तविक अभ्यर्थियों का चयन न होने से उनका मनोबल टूट जाता था। ऐसे फर्जी डिग्री जारी करने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ एसआईटी द्वारा गहनता से छानबीन कर मामला दर्ज किया गया एवं जांच प्रगति पर है। ऐसे निजी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, दलालों एवं कई लाभार्थियों को गिरफ्तार किया गया है और वे अभी भी जेल में बन्द हैं।
- एसओजी ने खेलों में फर्जी प्रमाण पत्र का गोरखधंधा उजागर कर इसमें संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस प्रकार एसआईटी द्वारा 173 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 136 आरोपी अभी भी जेल में हैं।
- दो आरोपियों द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित की गई सम्पत्ति को जब्त किये जाने के लिए जांच कर अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रवर्तन निदेशालय को लिखा गया है।
- राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में वांछित अभियुक्त यूनिक भाम्भू के परिवार का चूरू नगर परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ध्वस्त करवाया गया।
- वर्ष 2014 से लेकर आज तक विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में 111 राजकीय कर्मचारियों की संलिप्तता ज्ञात होने पर एसआईटी द्वारा उनके विरुद्ध प्रभावी विभागीय जांच कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। अनुचित साधनों के प्रयोग पर प्रभावी अंकुश ऐसे कार्यों में संलिप्त लोक सेवकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई से ही सम्भव है। पेपरलीक प्रकरणों में अभियुक्त 6 वनरक्षक तथा 11 अध्यापकों की सेवा समाप्त करवाई गई है। एसआईटी द्वारा 4 प्रकरणों में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कराये गये हैं, जिससे प्रकरणों में प्रभावी पैरवी हो सकेगी। ■

(आंकड़े 3 सितम्बर, 2024 तक अपडेटेड)

युवा उम्मीदों को पंख...

नए अवसर-नई पहचान

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवा शक्ति को अपनी पूर्ण क्षमता के साथ आगे बढ़ने और सपनों को साकार करने के भरपूर अवसर दिए हैं। युवा सपनों पर कुठाराघात करने वाले पेपर लीक माफिया पर लगाम कसने और सख्त कार्रवाई के साथ-साथ सरकारी और निजी क्षेत्र में 5 साल में 10 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।

5 वर्षों में 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

- युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति-2024 तथा कौशल क्षमता विकास के लिए नई स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जा रही है।
- स्टार्टअप स्थापित करने तथा उद्यमिता बढ़ाने के लिए अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है।
- इसके तहत चयनित स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपये तक की फंडिंग भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
- जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में एक हजार करोड़ रुपये की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर्स स्थापित किए जा रहे हैं।
- इस वर्ष लगभग 1 लाख पदों पर भर्तियां की जा रही हैं।
- राज्य स्तरीय 'मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव' में नवनियुक्त राज्य कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में प्रदेशभर से 20 हजार से अधिक नवनियुक्त अधिकारी-कर्मचारी जुड़े।
- 10 औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित कर रोजगार का सृजन होगा।
- राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट से खुलेंगे रोजगार के द्वार।
- दो साल में 1.50 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- भर्ती प्रक्रियाओं में अकारण विलम्ब समाप्त करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किए वार्षिक भर्ती कलेण्डर।

30 लगभग हजार नियुक्तियां

- 10 हजार पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी। 8 हजार पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई।
- 26 हजार पदों के लिए विज्ञापन जारी। इसके अलावा 29 हजार पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है, जिनके विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाएंगे।
- सहायक आचार्य के 1936, शारीरिक शिक्षकों के 247 एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के 247 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा संपन्न।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पालना में 2024-25 से महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली आरंभ। अब विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों और पाठ्यक्रमों का चुनाव कर सकता हैं।
- 37 नए राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे जिनमें 20 सह-शिक्षा, 13 कन्या एवं 4 कृषि महाविद्यालय शामिल हैं।
- प्रदेश में 1 हजार 27 करोड़ रुपये की लागत से 192 महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर अस्थायी भवनों में संचालित महाविद्यालयों को स्थायी भवन में संचालित किया जाएगा।
- स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की शुरुआत।
- किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अव्याना एविएशन एकेडमी के फ्लाइट स्कूल का उद्घाटन।
- केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तर्ज पर अग्निवीर युवाओं को पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक में नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान करने की घोषणा।

- युवाओं की स्किलिंग एवं अप्रेंटिसशिप के लिए पीएम पैकेज के अंतर्गत प्रदेश के ढाई लाख से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
- सरकारी नौकरियों में दस्तावेज सत्यापन विभागीय स्तर पर कराया जाएगा।
- विज्ञप्ति के बाद भी रिक्तियों की संख्या में अधिकतम 50 प्रतिशत वृद्धि के प्रावधान को बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया।
- चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के नियमों में परिवर्तन होगा। समान पात्रता परीक्षा (CET) क्वालीफिकेशन के लिए सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत एवं एससी-एसटी के लिए 35 प्रतिशत अंक किये जाने की घोषणा।
- प्रदेश के प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किए जा रहे हैं।
- निजी क्षेत्र में कॅरिअर मार्गदर्शन के लिए सभी संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र।
- ओलम्पिक में भाग लेने के लिए प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग, किट, कोच सहित सभी विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मिशन ओलम्पिक-2028 की घोषणा।
- जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स भी स्थापित किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों में एक हजार सरस मित्र।
- 2 वर्षों में 2 हजार नए डेयरी बूथ।
- Social Media Influencers हेतु 'नव प्रसारक' नीति लाई जाएगी। ■

संबल और सम्मान, खुशहाल किसान

भूमिपुत्रों का रखा ध्यान

किसान भारत की आत्मा हैं और उनकी खुशहाली से ही विकसित भारत की संकल्पना साकार होगी। हमारी केन्द्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के प्रत्येक किसान को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संकल्पित है। हम उन्हें पर्याप्त पानी की उपलब्धता और उनकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण समर्पण एवं सामर्थ्य के साथ कार्य कर रहे हैं।

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

आज प्रदेश के किसान समृद्धि के वाहक बन रहे हैं और राज्य सरकार उनकी आय बढ़ाने के हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने गेहूं की एमएसपी पर 125 रुपये का अतिरिक्त बोनस देते हुए 2400 रुपये प्रति क्विंटल करने और किसान सम्मान निधि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये करने जैसे कृषक कल्याण के अहम निर्णय किए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में किसान कल्याण सर्वोच्च है। उन्होंने देश में ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जिससे किसान आर्थिक रूप से सशक्त बनें और कृषि क्षेत्र की प्रगति दोगुनी रफ्तार से हो। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल में पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने

का काम किया है। वहीं, राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत राशि 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये की गई है। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 1 हजार 740 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम का वितरण किया गया तथा 9 हजार पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए।

किसानों को पर्याप्त पानी के प्रयास

पूर्ववर्ती राज्य सरकार के समय अटकी रही सिंचाई की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सरकार बनते ही पूरा करने में जुट गए। पीकेसी-ईआरसीपी और यमुना जल समझौते की क्रियान्विति किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम है। पीकेसी-ईआरसीपी से मध्यप्रदेश का पानी पूर्वी राजस्थान और ताजेवाला हेड वर्क्स से शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का पानी लाने पर तीव्र गति से काम जारी है। सरकार ने उदयपुर में देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना की नींव रखी है, जिससे आने वाले समय में उदयपुर की झीलों में जल उपलब्धता के साथ ही चित्तौड़गढ़, राजसमंद सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों की पेयजल की समस्या का समाधान भी होगा।

मोबाइल वेटरनरी इकाइयों का लोकार्पण

स्वस्थ पशुधन के लिए संकल्पित राज्य सरकार ने मोबाइल वेटरनरी इकाइयों (हेल्पलाइन नम्बर 1962) की शुरुआत की है। इसके जरिए पशुओं को शीघ्र चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध होंगी और पशुपालक समृद्ध होंगे। मुख्यमंत्री द्वारा 21 मोबाइल वेटरनरी इकाइयों को हरी झण्डी दिखाए जाने के साथ ही प्रदेश में 159 इकाइयों का लोकार्पण किया गया है। प्रत्येक एक लाख पशुओं पर एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट के लिए राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। यह पशुओं के सामान्य रोगों के उपचार में टेलिमेडिसन व्यवस्था एवं पशु प्रबंधन, पोषण आदि के लिए सलाह भी देगा। प्रत्येक ब्लॉक में मोबाइल इकाइयों द्वारा पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट के लिए एक पशु चिकित्सक, एक तकनीकी पशु चिकित्साकर्मी एवं एक ड्राइवर कम पशु परिचारक होंगे।

गेहूं की एमएसपी पर 125 रुपये का अतिरिक्त बोनस

किसान हित के लिए प्रतिबद्ध

- गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 5 लाख गोपालकों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण।
- 518 गोबाइल वेटरनरी इकाइयों से पशुओं को त्वरित चिकित्सकीय सेवाएं।
- गेहूं की एमएसपी पर 125 रुपये बोनस प्रदान कर एमएसजी 2400 रुपये की गई।
- 18 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाया।
- कृषि उपज मण्डी समिति निम्बाहेड़ा एवं छोटीसादड़ी में कार्यालय। भवन, किसान कलेवा भवन सहित अन्य विकास कार्यों की घोषणा।
- किसानों को बिजली बिलों में 16 हजार करोड़ रुपये का अनुदान।
- 50 हजार से अधिक किसानों के खेतों में सोलर पंप की स्वीकृति, 17523 स्थापित।
- 20 हजार किसानों को मिली फार्म पॉण्ड की सौगात।
- 1 हजार कस्टम हायरिंग केन्द्रों की होगी स्थापना।
- 76 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र।
- लगभग 93 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना।

किसान सम्मान निधि
6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपये की गई

- 70 हजार किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किए गए।
- चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क को समाप्त कर दिया गया।
- राज्य में 100 नई पैक्स का गठन किया जाएगा।
- 100 युवा एवं प्रगतिशील किसानों को मिलेगा विदेश में प्रशिक्षण।

आत्मनिर्भरता की राह पर शक्ति स्वरूपा

नारी सम्मान की पहचान बना राजस्थान

समृद्ध महिलाओं से ही समाज, प्रदेश व देश की खुशहाली संभव है। राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने पद संभालते ही कहा था कि राजस्थान की धरती मीराबाई, कालीबाई, पन्नाधाय, अमृता देवी जैसी वीर एवं भक्त नारियों की धरती है। इसलिए यहां की नारी को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करवाना सरकार की पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य में अब महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर होकर और सशक्त बन सकेंगी।

11.24 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में फरवरी में जैसलमेर में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की 11.24 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि एसएचजी में काम करने वाली लगभग 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तीकरण क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से न्यूनतम दर पर 1 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा।

450 रुपये में गैस सिलेंडर

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नये साल की सौगात देते हुए 1 जनवरी, 2024 से प्रदेश के पात्र परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की। योजना का लाभ 73 लाख परिवारों को मिला। सब्सिडी की राशि लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जा रही है। 1 सितंबर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा है।

महिला सुरक्षा

राज्य सरकार की प्राथमिकता

प्रदेशभर में

एंटी रोमियो स्क्वॉड

का गठन

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
- शेष रहे 174 पुलिस थानों में महिला डेस्क की स्थापना की गई।
- 'लखपति दीदी योजना' में इस वर्ष 5 लाख के स्थान पर 15 लाख महिलाओं का लक्ष्य।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनान्तर्गत महिलाओं को देय राशि 5000 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये की गई।

पुलिस फोर्स में महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी

रक्षाबंधन पर्व पर वीरांगनाओं का सम्मान

रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश की वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की कलाई पर रक्षासूत्र बांधा। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश की लगभग 1500 वीरांगनाओं को सम्मान स्वरूप 2100 रुपये, मिठाई, श्रीफल और शॉल भिजवाए।

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल–1 भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। ▪

ऊर्जा में सिरमौर, सरप्लस की ओर

अपूर्व निवेश की तैयारी

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में असीम संभावनाएं हैं। इसी क्रम में 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 'आदर्श सौर ग्राम' स्थापित किए जाएंगे। ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न पीएसयू के साथ 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं। इनमें से चार परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कैबिनेट की मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है।

ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी निर्णयों से तीन साल बाद राजस्थान बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सरप्लस की स्थिति में आ जाएगा और प्रदेश बिजली खरीदने के स्थान पर दूसरे राज्यों को बिजली बेचने में सक्षम हो जाएगा। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में करीब सवा दो लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। राज्य सरकार ऊर्जा क्षेत्र से सम्बंधित योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है।

राज्य को सरप्लस एनर्जी स्टेट बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 हैक्टेयर तथा फलौदी जिले में 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हैक्टेयर भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई।

बीकानेर जिले में एक-एक हजार मेगावाट के दो तथा 450 मेगावाट का एक सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। पहले सोलर पार्क के लिए पूगल तहसील के ग्राम सूरासर में लगभग 1881 हैक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी

गई। इसी तरह एक हजार मेगावाट के दूसरे सोलर पार्क के लिए दो हजार हैक्टेयर भूमि आवंटित की जायेगी, जिसमें से 1194 हैक्टेयर भूमि सूरासर तथा लगभग 807 हैक्टेयर भूमि ग्राम भणावतावाला में स्थित है।

बीकानेर जिले में ही 450 मेगावाट के तीसरे सोलर पार्क की स्थापना के लिए छत्तरगढ़ तहसील के ग्राम सरदारपुरा में 900 हैक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। ये सोलर पार्क राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय (केन्द्र सरकार) की सौर पार्क योजना के अन्तर्गत 3 चरणों में विकसित किए जाएंगे।

सिरे चढ़ी विकास परियोजनाएं

- बीकानेर जिले में बरसिंगसर 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना, लागत 1400 करोड़ रुपये।
- फतेहगढ़-द्वितीय और भादला-द्वितीय में आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में सुदृढ़ीकरण, एसईजेड 8.1 गीगावाट ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण, चरण-द्वितीय भाग-बी के अंतर्गत राजस्थान (8.1 जीडब्ल्यू) में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से

बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना।

- बीकानेर में विकसित 300 मेगावाट की एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नोखरा सोलर पीवी परियोजना, लागत 2700 करोड़।

राज्य सरकार एवं हुडको के बीच एमओयू

राज्य में ऊर्जा, पेयजल और सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय संसाधन सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इसके तहत हाउसिंग एण्ड अरबन डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) एवं राज्य सरकार के बीच एक लाख करोड़ रुपए का एमओयू किया गया है। इसके तहत आगामी 5 वर्षों तक पानी, सिंचाई और बिजली जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को प्रति वर्ष 20 हजार करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

पीएम सूर्य घर... असली गेमचेंजर

राज्य में पीएम सूर्य घर योजना के अन्तर्गत पोर्टल पर 1 लाख से अधिक का पंजीकरण हो चुका है। केन्द्र सरकार की 'पीएम सूर्य घर योजना' के तहत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। केन्द्र सरकार घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए बैंकों से कम ब्याज दरों पर आवेदक को ऋण उपलब्ध करवाएगी। राज्य सरकार द्वारा भी 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई गई हैं। इसके तहत 3 किलोवाट तक Solar Plant लगाने पर 78 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत हर जिले में 'आदर्श सौर ग्राम' बनाया जाएगा, जिनमें 2 MW तक के विकेन्द्रीकृत सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना हेतु 40 प्रतिशत अनुदान देय।

रोजगार का सृजन, कम होगा कार्बन उत्सर्जन

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के अनुसार सोलर प्रोजेक्ट्स से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ ही क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। साथ ही, ये प्रोजेक्ट्स पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएंगे और सालाना लगभग 2 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इन सोलर पार्कों में अत्याधुनिक सौर पैनल्स और ग्रिड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिससे ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगी।

ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमिता के नए युग की शुरुआत

पीएम कुसुम योजना से प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमिता के नए युग की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग के 7,167 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। इनमें 1863 करोड़ के कार्य प्रसारण क्षेत्र में हैं तथा शेष डिस्कॉम्स के हैं। शिलान्यास किए गए 608 सोलर प्लांट्स के जरिए 5 हजार 254 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 1501 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। योजना के माध्यम से करीब 2 हजार नए उद्यमी सौर ऊर्जा उत्पादन से जुड़ सकेंगे और आने वाले समय में उद्यमिता की इस अलख से प्रदेश में हर गांव–ढाणी रोशन होगी।

निर्बाध आपूर्ति के लिए राज्य के विद्युत निगमों एवं केन्द्रीय उपक्रमों के मध्य एमओयू-पीपीए

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तापीय और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, प्रसारण तंत्र, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा अन्य विकास कार्यों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये के एमओयू एवं पीपीए हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य में 31 हजार 825 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन की विभिन्न परियोजनाओं सहित ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए राज्य के 3 विद्युत निगमों एवं 6 केन्द्रीय उपक्रमों के उच्चाधिकारियों के बीच 5 एमओयू तथा एक पॉवर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही, राज्य में अवसंरचना क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न विभागों, उपक्रमों तथा संस्थाओं के वित्त पोषण के लिए आरईसी लिमिटेड और राज्य सरकार के बीच भी 20 हजार करोड़ रुपये का एक एमओयू किया गया।

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी तथा आरवीयूएनएल के बीच संयुक्त उपक्रम

प्रदेश में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लि. तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के मध्य संयुक्त उपक्रम कंपनी की स्थापना हेतु हस्ताक्षर किए गए। इस कंपनी से राज्य में 25 हजार मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को गति मिलेगी और राज्य में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा।

आधी से भी कम दर पर मिलेगी बिजली

जैसलमेर के भैसाड़ा गांव में एनटीपीसी रिन्यूबल एनर्जी लि. की 160 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण भी किया गया। इस परियोजना से राज्य को 2 रुपये 8 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रतिवर्ष लगभग 44 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी। यह दर एनर्जी एक्सचेंज से वर्तमान में की जा रही खरीद की औसत 4 रुपये 76 पैसे प्रति यूनिट की दर से बहुत कम है।

2.24
लाख करोड़ रुपये के निवेश एमओयू

प्रत्येक जिले में बनेंगे
आदर्श सौर ग्राम

अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 के प्रावधानों में संशोधन

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 एवं राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के प्रावधानों में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इससे सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन डीएलसी दर के 7.5 प्रतिशत पर किया जा सकेगा। साथ ही, अब 2 हैक्टेयर भूमि पर एक मेगावाट की दर से सौर ऊर्जा उत्पादन हो सकेगा। ■

सौर ऊर्जा क्षमता श्रेणी में राजस्थान प्रथम

गुजरात के गांधीनगर में चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो (री-इन्वेस्ट 2024) में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 200 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया गया। राज्य ने कुल सोलर ऊर्जा क्षमता श्रेणी में सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करते हुए देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की श्रेणी में राजस्थान द्वितीय स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हीरालाल नागर ने केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी के हाथों से 16 सितम्बर को ये पुरस्कार ग्रहण किए। ■

हर घट जल की 'हठ' पूरी

दशकों से लंबित जल परियोजनाएं साकार

हमारी सरकार पूर्वी राजस्थान के लिए संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना (एकीकृत ईआरसीपी) के साथ ही शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता, दक्षिण राजस्थान के जिलों के लिए देवास परियोजना का धरातल पर क्रियान्यवन कर रही है। पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना पूर्वी राजस्थान में सिंचाई एवं पेयजल के लिए जीवनरेखा सिद्ध होगी। सरकार द्वारा इस दिशा में तीव्रता से कार्य करते हुए भू-अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा प्रथम चरण के कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं।

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

प्रदेश में सरकार बनते ही संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना (एकीकृत ईआरसीपी) की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार का केन्द्र और मध्यप्रदेश के साथ एमओयू किया गया। पीकेसी-ईआरसीपी से मध्यप्रदेश एवं राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा एवं एक स्वर्णिम युग का उदय होगा। दोनों राज्यों के विकास के लिए यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। इससे राजस्थान के लगभग 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई जल एवं लगभग 40 प्रतिशत आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही, भूजल के स्तर में भी वृद्धि होगी। इसी क्रम में ताजेवाला हेड वर्क्स से शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का पानी लाने की कई दशकों से लंबित परियोजना के लिए भी राज्य सरकार द्वारा केन्द्र एवं हरियाणा सरकार के साथ ऐतिहासिक त्रिपक्षीय एमओयू किया गया। सरकार ने उदयपुर में देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना की नींव रखी है, जिससे आने वाले समय में उदयपुर की झीलों में जल उपलब्धता के साथ ही चित्तौड़गढ़, राजसमंद सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों की पेयजल की समस्या का समाधान भी होगा।

25 लाख किसान परिवारों को
सिंचाई जल एवं
लगभग 40% आबादी
को पेयजल उपलब्धता के लिए
पीकेसी-ईआरसीपी

केन्द्र, राजस्थान और मध्यप्रदेश के मध्य एमओयू

बहुप्रतिक्षित संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना (एकीकृत ईआरसीपी) की संयुक्त डीपीआर बनाने के लिए केन्द्र, राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार के बीच श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। तत्कालीन केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

21 जिलों की जीवन रेखा

संशोधित पार्वती-कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना (एकीकृत ईआरसीपी) का दायरा पहले से ज्यादा विस्तृत होगा। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए तैयार की गई इस परियोजना में अब 21 जिले कवर होंगे। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, गंगापुरसिटी, खैरथल तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, ब्यावर, अजमेर एवं केकड़ी जिले को परियोजना का लाभ मिलेगा। इन जिलों की लगभग 3.25 करोड़ आबादी को इस परियोजना से अगले 5 दशक तक पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। आजादी के बाद यह प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना होगी।

बांधों का क्षमतावर्द्धन और पुनर्रुद्धार

एमओयू के अनुसार परियोजना में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनैरा बैराज, गेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र, ईसरदा बांध का क्षमता वर्धन एवं पूर्वनिर्मित 26 बांधों का पुनर्रुद्धार किया जाएगा।

तीन जिलों को मिलेगा यमुना का पानी

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, तत्कालीन केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में हुए एक त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर से ताजेवाला से प्रवाह प्रणाली के क्रम में डीपीआर बनाने पर सहमति बनी। इस योजना के मूर्त रूप लेने के बाद राजस्थान के तीन जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनूं को ताजेवाला हेड-वर्क्स से यमुना नदी का पानी मिल सकेगा और बारिश में व्यर्थ बह जाने वाले जल का भी समुचित उपयोग हो सकेगा। यह परियोजना विगत तीन दशक से अटकी थी।

उदयपुर की झीलें वर्षभर रहेंगी लबालब

झीलों की नगरी उदयपुर में वर्ष पर्यन्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना की शुरुआत की गई है। इससे उदयपुर की वर्षपर्यन्त पेयजल की मांग पूरी होगी। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने उदयपुर के गोगुंदा में देवास परियोजना के तृतीय व चतुर्थ बांध एवं टनल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। देवास तृतीय परियोजना के तहत गोगुंदा तहसील के नाथियाथाल गांव के निकट 703 मिलियन घन फीट क्षमता के देवास तृतीय बांध का निर्माण करवाया जाएगा। इससे 11.04 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर आकोदड़ा बांध में पानी लाया जाएगा। आकोदड़ा बांध से पिछोला झील में जल अपवर्तन होगा।

देवास चतुर्थ परियोजना में गोगुंदा तहसील के अंबावा गांव के निकट 390 मिलियन घन फीट क्षमता के देवास चतुर्थ बांध का निर्माण किया जाएगा। इसे 4.3 किलोमीटर सुरंग का निर्माण कर देवास तृतीय बांध से जोड़ दिया जाएगा। करीब 1690 करोड़ की परियोजना को 44 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ■

बरसों का सपना साकार, आपका बहुत-बहुत आभार

पीकेसी–ईआरसीपी परियोजना प्रारम्भ होने से हर्षित प्रदेशवासियों ने विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

पहला सुख – उत्तम स्वास्थ्य, सुलभ उपचार

चिकित्सा ढांचे में व्यापक सुधार

मा वाउचर योजना

में गर्भवती महिलाओं को

1,161 निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्र पर

निःशुल्क प्रसव पूर्व सोनोग्राफी सुविधा

मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) का दायरा अब और बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत राजकीय अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों का नेटवर्क अब गांवों तक भी उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना में पोर्टेबिलिटी की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। इससे अन्य राज्यों के नागरिक भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे और राजस्थान के रोगी अन्य राज्यों में भी इलाज प्राप्त कर सकेंगे।

मा वाउचर से निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा

श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मा) वाउचर योजना का 17 सितम्बर को शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाएं 1,161 निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी करा सकेंगी। योजना पर सरकार 10 करोड़ रुपये से अधिक प्रतिवर्ष व्यय करेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

बजट में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आईपीडी के साथ डे-केयर पैकेज जोड़ने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का ओपीडी में इलाज संभव होगा। साथ ही हाई-वे पर 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाना, आशाओं के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि करना जैसे संवेदनशील निर्णय लिए गए। कैंसर के उपचार हेतु 73 डे केयर पैकेज लागू किए गए हैं।

चिकित्सा विभाग के तीन अभियानों का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विभाग के तीन अभियानों का शुभारम्भ किया है। उन्होंने पोलियो दिवस के अवसर पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर प्रदेश में 'राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान' की शुरुआत की। वहीं, 'स्टॉप डायरिया अभियान-2024' एवं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 'आभा आईडी बनाओ' अभियान का भी शुभारम्भ किया।

एम्स की तर्ज पर प्रदेश में बनेगा आरआईएमएस

आरयूएचएस का उन्नयन करते हुए एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम-2018 के अंतर्गत इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन किए जाने की भी घोषणा की गई।

अब हिंदी माध्यम में भी आयुर्विज्ञान की शिक्षा

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बजट घोषणा को पूरा करते हुए हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी माध्यम में भी चिकित्सा शिक्षा प्रारम्भ किए जाने की सूचना जारी की है। पहले चरण में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध डॉ. सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, जोधपुर एवं बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में इस सुविधा का शुभारम्भ किया गया है।

स्वास्थ्य सबसे पहले

- आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के प्रत्येक पात्र नागरिक को 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा।
- श्रीगंगानगर एवं मेडिकल कॉलेज कोटा में कैंसर मरीजों के लिए लीनियर एक्सलरेटर मशीनें उपलब्ध करवाने की घोषणा।
- अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में पीडियाट्रिक ब्लॉक, मल्टीलेवल पार्किंग और गर्ल्स पीजी हॉस्टल की शुरुआत।
- जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का शिलान्यास।
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 'आयुष्मान मॉडल CHC' स्थापित किए जाने की घोषणा।
- 1 हजार 500 चिकित्सकों तथा 4 हजार नर्सिंग कर्मियों के नए पद। ■

भक्ति की भावना प्रदेश में खुशहाली की कामना

राम हमारी आस्था के केन्द्र हैं, वे हमारे रोम-रोम में बसे हैं। इस दुनिया में सब कुछ करने वाले राम हैं। सब राम की ही महिमा है। पहले अयोध्या में भगवान रामलला के टेंट में दर्शन किए थे, अब इस भव्य और दिव्य मंदिर में भगवान के दर्शन करना अभिभूत करने वाला है।

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा अपने मंत्रिपरिषद् के सदस्यों और विधायकों के साथ पहली बार अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में रामलला के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर देश-प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अयोध्या पहुंचे और श्रीरामलला के द्वार पर पहुंचकर भक्ति भाव में खो गए।

अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू

प्रदेश के सात संभाग मुख्यालयों जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर से अयोध्या के लिए रोडवेज बस सेवा की शुरुआत की गई। इसके साथ ही अयोध्या के लिए 1 फरवरी को हवाई सेवा भी शुरु की गई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना में अयोध्या के दर्शन शामिल किए जा चुके हैं। साथ ही, राज्य से अयोध्या के लिए आस्था ट्रेन भी शुरू हो चुकी है।

महत्वपूर्ण घोषणाएं

- राजस्थान एवं मध्यप्रदेश सरकार मथुरा से सांदीपनि आश्रम तक जाने वाले मार्ग 'श्रीकृष्ण गमन पथ' को संयुक्त रूप से विकसित करेंगी।
- प्रदेश में देवस्थान विभाग के 593 मंदिरों में विद्युत सज्जा, महाआरती, संत-महंत एवं पुजारियों का सम्मान।
- छह औद्योगिक क्षेत्रों में 'श्रीराम-जानकी औद्योगिक क्षेत्र' क्रियाशील किया गया।
- 'श्रीराम-जानकी आवासीय योजना' में 208 भूखंडों का आवंटन।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिरों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना

इस वर्ष के प्रारंभ में लगभग 3 हजार तीर्थ यात्रियों को श्री राम लला के दर्शन हेतु अयोध्या की यात्रा करवाई जा चुकी है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल 36 हजार तीर्थ यात्रियों में से 15 हजार तीर्थ यात्रियों को अयोध्या, 15 हजार तीर्थ यात्रियों को अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। साथ ही, 6 हजार तीर्थ यात्रियों को काठमांडू (नेपाल) स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की हवाईजहाज से तीर्थ यात्रा भी करवायी जाएगी। इन तीर्थ यात्रियों के आवागमन, परिवहन, भोजन, आवास व्यवस्था इत्यादि की समस्त व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा की जाएंगी। ■

फील्ड पर नजर दिख रहा असर

सुशासन के अपने संकल्प के तहत कई बार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा स्वयं फील्ड में उतरे और निरीक्षण कर चाक-चौबंद व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया। भीषण गर्मी के दौरान जलापूर्ति व्यवस्था की जांच करनी हो या पूर्वी राजस्थान में हवाई सर्वेक्षण कर जल भराव की स्थिति ज्ञात करनी हो या फिर शासन सचिवालय का औचक निरीक्षण, मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक तंत्र को अपने निरीक्षणों से चुस्त बनाये रखा।

आरयूएचएस, प्रताप नगर का दौरा कर भविष्य की प्लानिंग पर अधिकारियों को निर्देश

जल अभाव के समय पम्प हाउस का निरीक्षण

प्रस्तावित बस अड्डा साइट का निरीक्षण

जल भराव के समय क्षेत्र का दौरा

अतिवृष्टि के समय पूर्वी राजस्थान का हवाई सर्वेक्षण

RISING
RAJASTHAN
9-10-11 DEC 2024 • JAIPUR
REPLETE • RESPONSIBLE • READY

राइजिंग राजस्थान
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट
2024

इन्वेस्टमेंट समिट का उद्देश्य देशी-विदेशी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करना है। सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिए हर संभव पहल कर रही है और इसी क्रम में आयोजित किए जा रहे इस निवेश सम्मेलन से प्रदेश के विकास के साथ रोजगार के भरपूर अवसर सृजित होंगे।

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

राजस्थान के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने और राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन करेगी। इस त्रि-दिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश-विदेश की बड़ी-छोटी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आकर काम करने के लिए आकर्षित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग-धंधे लगाने में मदद करना और सुविधाएं मुहैय्या कराना है।

इस ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, ऑटो और ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल्स), इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रो-केमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन और आईटी सहित विभिन्न विषयों पर विशेष सत्रों का आयोजन होगा।

राजस्थान सरकार के तत्वाधान में 'राइजिंग राजस्थान' इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन उद्योग विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन (बीआईपी) और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम (रीको) द्वारा किया जा रहा है। इसका नोडल विभाग बीआईपी है। साथ ही साथ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) निवेश शिखर सम्मेलन का समिट इंडस्ट्री पार्टनर है और इसके आयोजन में मदद कर रहा है।

हैं तैयार हम ...

RISING RAJASTHAN
9-10-11 DEC 2024 • JAIPUR
REPLETE • RESPONSIBLE • READY

ब्राण्डिंग के लिए लोगो की लांचिंग

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 'राइजिंग राजस्थान' का लोगो लॉन्च किया है, ताकि उसकी देश और विदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण मंचों पर अलग ब्रांड आइडेंटिटी बन सके। 'राइजिंग राजस्थान' के तहत राज्य सरकार द्वारा देश और विदेश के विभिन्न शहरों में निवेशक रोड शो किए जा रहे हैं, ताकि विश्वभर के निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने का न्योता दिया जा सके।

राइजिंग राजस्थान 'वॉर रूम'

मुख्यमंत्री के निर्देश पर राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन के लिए वॉर रूम स्थापित किया गया है जहां उचित संसाधनों के साथ विशेषज्ञ टीम आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध रूप से पूरा करने में जुटी है। आयोजन का सभी माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। विदेशों से आने वाले निवेशकों के लिए इन्वेस्टमेंट इन्विटेशन पैकेज तैयार किए जा रहे हैं।

प्रदेश में 'सिंगल-प्वाइंट निवेशक इंटरफेस' लॉन्च

राजस्थान में निवेश के इच्छुक निवेशकों के लिए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राज्य सरकार का 'सिंगल-प्वाइंट निवेशक इंटरफेस' भी लॉन्च किया है, ताकि निवेशक सरकार के साथ आसानी से एमओयू कर सकें। इस 'सिंगल-प्वाइंट निवेशक इंटरफेस' प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेशक राज्य सरकार के साथ एमओयू के लिए अपनी मंशा ऑनलाइन जाहिर कर सकते हैं। उनके प्रस्तावों को मंजूरी भी ऑनलाइन दी जाएगी। इस पहल के लॉन्च किये जाने के तुरंत बाद 'राइजिंग राजस्थान' के आयोजन के लिए नोडल विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को 8000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। इतना ही नहीं इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने के 2 हफ्ते के भीतर ही ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, जो इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का नोडल विभाग है, को 5.21 लाख करोड़ रुपये के निवेश योग्य प्रस्ताव मिल चुके हैं। ऐसा राज्य में पहली बार हुआ है।

वेबसाइट लॉन्च

'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला 'इन्वेस्टर मीट' 30 अगस्त को भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की आधिकारिक वेबसाइट - https://rising.rajasthan.gov.in भी लॉन्च की।

विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के उभरने से राजस्थान के लिए विकास के नए अवसर खुले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश को विकास के एक नए युग में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके तहत, हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राजस्थान को **350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनाने का है। राजस्थान के समग्र विकास को लेकर बनायी गई हमारी नीतियां विश्वसनीय हैं और निवेशकों के अनुकूल हैं, ताकि राज्य और प्रदेशवासी विकास के एक नए दौर में पहुंच सकें। 'राइजिंग राजस्थान' इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के माध्यम से राजस्थान में उपलब्ध इन अवसरों को हम देश और विदेश के निवेशकों को प्रस्तुत करेंगे। हम चुनौतियों से घबराते नहीं हैं और इसलिए अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में ही हम 'राइजिंग राजस्थान' निवेश सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं।

आयोजन से प्रदेश में आने वाले निवेश को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार की ओर से निवेशकों की हर संभव मदद की जाएगी। निवेशकों को उनके द्वारा किए जाने वाले निवेश संबंधित क्षेत्र की सभी जानकारी पहले ही उपलब्ध करवायी जाएगी, ताकि उन्हें निवेश को धरातल पर मूर्तरूप देने में आसानी रहे। हमने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग व इस आयोजन से जुड़े समस्त स्टेक हॉल्डर्स को निर्देशित किया है कि 'राइजिंग राजस्थान' निवेश शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी टीम भावना के साथ कार्य करें।

राइजिंग राजस्थान प्रदेश के औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान में निवेश करने वाले उद्यमियों को भूमि, बिजली एवं पानी की उपलब्धता समयबद्ध एवं नीतिगत रूप से सुनिश्चित करवाई जाएगी, जिससे निवेश धरातल पर मूर्तरूप ले सके।

भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री

अवसरों का नया 'डेस्टिनेशन'

देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में अपार मात्रा में प्राकृतिक खनिज और अन्य संसाधन उपलब्ध हैं। साथ ही, राज्य में स्किल्ड वर्कफोर्स की भी कमी नहीं है और यह राज्य रणनीतिक रूप से उत्तर भारत के प्रमुख उपभोक्ता बाजारों के करीब है। पिछले एक दशक में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडॉर (डीएमआईसी) और वेस्ट्रन फ्रेट कॉरीडॉर जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी परियोजनाएं यहां चल रही हैं। राज्य और केंद्र सरकार के बीच सकारात्मक तालमेल है, जो विकास परियोजनाओं की निरंतर प्रगति सुनिश्चित करता है और राज्य में उद्योगों के अनुकूल वातावरण बनाने में भी मदद करता है। राजस्थान सरकार निवेशकों की परेशानियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और 'राइजिंग राजस्थान' उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है, ताकि राज्य में निवेश के नए अवसर आते रहें। ■

जापान और कोरिया की यात्रा के लिए रवाना होते मुख्यमंत्री

जापान इन्वेस्टर मीट में शामिल होते मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

कोरिया इन्वेस्टर मीट में उद्बोधन देते मुख्यमंत्री

परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन

RISING RAJASTHAN

सतत् प्रयास देश-विदेश, पुख्ता हुआ निवेश

'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत मुम्बई में 30 अगस्त, 2024 को हुई पहली 'इन्वेस्टर मीट'

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला से मुलाकात

गृहमंत्री श्री अमित शाह से आत्मीय भेंट

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन को पुष्प गुच्छ भेंट

विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर से मुलाकात

'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024

प्रथम 'इन्वेस्टर मीट' मुम्बई

30 अगस्त, 2024

5 वर्षों में राजस्थान बनेगा 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

राज्य में निवेश के लिए 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू हस्ताक्षरित

'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला 'इन्वेस्टर मीट' भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में 30 अगस्त को आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित 'इन्वेस्टर मीट' के दौरान राजस्थान में निवेश के लिए राज्य सरकार के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और विभिन्न उद्योगपतियों के बीच 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

'इन्वेस्टर मीट' में उद्योग एवं व्यापार जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं। इस दौरान अक्षय ऊर्जा, सीमेंट, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, नागरिक उड्डयन और आईटीआई के अपग्रेडेशन जैसे कई क्षेत्रों में निवेश के लिए एमओयू किये गए। इन कंपनियों और औद्योगिक समूहों में अदानी ग्रुप, वेदांता ग्रुप, जेएसडब्लू ग्रुप, टाटा ग्रुप, वारी ग्रुप, डालमिया ग्रुप और स्टार सीमेंट शामिल हैं।

निवेशकों और कारोबारियों को आमंत्रण

2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 'विकसित राजस्थान' का होना जरूरी है। राजस्थान अपार संभावनाओं से लैस प्रदेश है जहां प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं। इसके अलावा हमारे राज्य में स्किल्ड वर्कफोर्स की भरमार है और यहां निवेश के असीमित अवसर हैं। मैं निवेशक समुदाय, कॉरपोरेट्स और बाकी अन्य संस्थानों को हमारे खूबसूरत राज्य में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए और राजस्थान सरकार की निवेशकों के अनुकूल नेक्स्ट जेनरेशन नीतियों का लाभ उठाइए।

भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री

मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने इस मौके पर कहा कि "राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत हमने स्ट्रेटिजिक सेक्टर्स और राज्य में निवेश के लिए मौजूद अवसरों की पहचान कर रखी है। 'विकसित राजस्थान'@2047 की दिशा में यह बात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आजकल राजस्थान सरकार महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय कुछ ही घंटों में ले लेती है, जबकि पहले ऐसे निर्णय लेने में महीनों और वर्षों का समय लग जाता था। निवेशकों से मिली अब तक की जबरदस्त प्रतिक्रिया से पता चलता है कि राजस्थान और इसकी क्षमता पर उनके विश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारी कोशिश है कि यह गति बरकरार रहे।"

'राजस्थान राइजिंग' ग्लोबल समिट 2024 के पहले घरेलू 'इन्वेस्टर मीट' में भाग लेने वाली प्रमुख व्यापारिक हस्तियों में अदानी सीमेंट्स और अदानी पोर्ट्स, एसईजेड और लॉजिस्टिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री करण अदानी, टाटा केमिकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री आर. मुकुंदन, टाटा पावर के प्रबंध निदेशक और सीईओ डॉ. प्रवीर सिन्हा, हिंदुस्तान जिंक के सीईओ और वेदांता लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री अरुण मिश्रा, जेके सीमेंट के उप प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री माधव सिंघानिया, जेएसडब्लू एनर्जी के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शरद महेंद्रा, सेंरेंटिका रिन्यूएबल्स के सीईओ अक्षय हीरानंदानी और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के पश्चिमी क्षेत्र की अध्यक्ष सुश्री स्वाति सालगांवकर शामिल थे।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना को नया स्वरूप

"राजस्थान में केवल एक ही वीआईपी है, वह है राजस्थान में निवेश करने वाला निवेशक। राजस्थान के विकास के अपने सपने को साकार करने के लिए हमारे पास राजनीतिक इच्छाशक्ति है। इतने कम समय में निवेशकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने हमें बड़े सपने देखने के लिए पंख दिए हैं और 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को सफल बनाने के लिए हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है।"

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, उद्योग मंत्री

4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू

"समिट के पहले 'इन्वेस्टर मीट' में ही राज्य में 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। निवेशकों और उद्योग जगत का दृढ़ विश्वास यह बताता है कि राजस्थान में संभावनाएं अपार हैं। अगले 5 वर्षों में ही हम राज्य को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बना सकने में सक्षम होंगे।"

भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री

देश के कई बड़े उद्योगपतियों की मुख्यमंत्री से मुलाकात

इस 'इन्वेस्टर मीट' के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शर्मा देश के कई बड़े उद्योगपतियों से मिले और उन्हें राजस्थान में निवेश करने तथा निवेशकों के लिए बनाए जा रहे अनुकूल ईको सिस्टम और नीतियों का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में महिंद्रा एवं महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनन्द महिंद्रा, जेएसडब्लू ग्रुप के चेयरमैन श्री सज्जन जिंदल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के भारत और दक्षिण एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कुमार वेंकटसुब्रमण्यम, वेदांता ग्रुप की नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन सुश्री प्रिया अग्रवाल, एस्सार ग्रुप के ग्रुप डायरेक्टर श्री अंशुमान रुइया, अवादा ग्रुप के चेयरमैन श्री विनीत गित्तल, इमैजिका एंटरटेनमेंट के सीईओ श्री धीमंत बख्शी, और यूपीएल लिमिटेड के श्री राज तिवारी शामिल हैं। इस दौरान राजस्थान सरकार के कई शीर्ष अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) श्री शिखर अग्रवाल, उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव और रीको के अध्यक्ष श्री अजिताभ शर्मा, उद्योग विभाग और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के आयुक्त श्री रोहित गुप्ता शामिल थे। ■

'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024

प्रथम अंतरराष्ट्रीय 'इन्वेस्टर मीट' प्रथम दिवस : सियोल

दक्षिण कोरिया

9 सितम्बर, 2024

मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए 9 सितम्बर को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लिया। इस इन्वेस्टर मीट के जरिए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने दक्षिण कोरिया के व्यापारिक समुदाय और निवेशकों को राजस्थान में निवेश हेतु आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था को मौजूदा 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना कर 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने के अपनी सरकार के एजेंडे को रेखांकित किया और निवेशकों को आश्वासन दिया कि राज्य में 'व्यापार करने में आसानी' हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रक्रियाओं और नीतियों में लगातार सुधार किया जा रहा है"। उन्होंने स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और दक्षिण कोरिया के व्यापारिक समुदाय के सदस्यों को राजस्थान में कारोबार करने के लिए आमंत्रित किया।

इन्वेस्टर मीट के अलावा, मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कई बड़ी दक्षिण कोरियाई कंपनियों और एसोसिएशन (जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल्स, स्टार्टअप्स और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल हैं) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की। इसमें पॉस्को इंटरनेशनल, एसजी कॉरपोरेशन (दक्षिण कोरिया की एस्फॉल्ट और कंक्रीट निर्माता कंपनी), जीएस ईएंडसी (दक्षिण कोरिया की अक्षय ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज कंपनी), हनवा सॉल्यूशन (केमिकल कंपनी) और जियोनबुक क्रिएटिव इकोनॉमी इनोवेशन सेंटर (जेसीसीईआई) है जो स्टार्टअप्स के लिए इन्क्यूबेटर का काम करती है, के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठकें शामिल हैं। इसके अलावा, इन्वेस्टर मीट के दौरान मौजूद कई निवेशकों ने राज्य में निवेश करने में रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री के साथ गए इस उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल, उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अजिताभ शर्मा और राजस्थान सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।

सभी क्षेत्रों में दीर्घकालिक साझेदारी की आकांक्षा

राजस्थान सरकार दक्षिण कोरिया को केवल निवेश के स्रोत के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि दक्षिण कोरिया के व्यापारिक समुदाय के साथ सभी क्षेत्रों में एक मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी बनाने की आकांक्षा रखती है। निवेशकों के अनुकूल माहौल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत राज्य सरकार जल्द ही कई नई नीतियां लाने जा रही है, जो राज्य में व्यापार और कारोबार के माहौल को और बेहतर बनाएंगी। इनमें नई औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, एमएसएमई नीति और एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) नीति शामिल हैं।

भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री

कोरियाई कम्पनियों की राज्य में बेहतर सड़कों की पेशकश

पॉस्को इंटरनेशनल और एसजी कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री से मुलाकात की और राजस्थान में एस्फॉल्ट यूनिट लगाने में रुचि दिखाई और अपने उत्पादों के जरिए राज्य में "बेहतर सड़कें" बनाने की पेशकश की। इस बैठक में प्रदेश में निवेश हेतु सब्सिडी, बुनियादी ढांचा सेवाओं, कच्चे माल की खरीद और अन्य आवश्यकताओं के संबंध में अपनी अपेक्षाएं भी उन्होंने सरकार से साझा कीं। जेसीसीईआई के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दोनों पक्षों द्वारा उद्यमिता के बारे में ज्ञान के आदान-प्रदान

आशाजनक निवेश और व्यापार गंतव्य

राजस्थान भारत में एक आशाजनक निवेश और व्यापार गंतव्य के रूप में उभर रहा है। कारोबार और व्यापार में विस्तार के लिए राज्य अनुकूल नीतियां और वातावरण बनाने में लगा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट 2024 राज्य में नए व्यावसायिक उपक्रमों की खोज के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करेगा।

अमित कुमार, दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत

मैं राजस्थान का प्रतिनिधि, आप सभी को आमंत्रण

संस्कृति और त्योहारों के मामले में भारत और दक्षिण कोरिया, दोनों देशों में बहुत समानता है। राजस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर भारत की ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति वाले हमारे राज्य में निवेश के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। आज राजस्थान भारत में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हमारा राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और अन्य कई सुविधाओं से सुसज्जित है। हमारी सरकार आपके निवेश की यात्रा में हर कदम पर सहयोग करने के लिए तैयार है। साथ मिलकर, हम राजस्थान के लिए एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं और दोनों महान देशों के बीच की मित्रता को और मजबूत कर सकते हैं।

भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री

और स्टार्टअप्स को अपने व्यवसाय के विकास में मदद करने के अवसरों पर विचार किया गया।

पर्यटन संभावनाओं पर विशेष इन्वेस्टर रोड शो

राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष इन्वेस्टर रोड शो का भी यहां आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश में अवस्थित यूनेस्को की सूची में शामिल 9 विश्व हेरिटेज साइट्स, राज्य के किले और महल, वन और वन्यजीव, मेले और त्योहार, राजस्थान में होने वाली शादियां और 'पैलेस ऑन व्हील्स' शामिल हैं। शो में बताया गया कि 'पैलेस ऑन व्हील्स' एक हेरिटेज ट्रेन है जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को राजस्थान के बेहतरीन स्थलों की सैर कराती है और यह 7 दिनों में राज्य भ्रमण करने का सबसे अच्छा तरीका है। ■

'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024

प्रथम अंतरराष्ट्रीय 'इन्वेस्टर मीट' का

द्वितीय दिवस

दक्षिण कोरिया

10 सितम्बर, 2024

मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दूसरे दिन 10 सितम्बर को कई दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने प्रदेश में अवसरों की तलाश करने और राज्य में अपने व्यवसाय का विस्तार करने में रुचि दिखायी। इसमें सैमसंग हेल्थकेयर, एलएक्स इंटरनेशनल, ओरियन कॉरपोरेशन, ह्योसंग कॉरपोरेशन के साथ-साथ कोरियन स्टोन एसोसिएशन सहित कई अन्य दक्षिण कोरियाई कंपनियां शामिल हैं।

प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के दौरान, सैमसंग हेल्थकेयर ने राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर AI आधारित नए हेल्थकेयर डिवाइसेज उपलब्ध कराने में अपनी रुचि दिखायी। वहीं, ओरियन कॉरपोरेशन ने अपने भिवाड़ी गैन्यूफैक्चरिंग प्लांट की चर्चा करते हुए राजस्थान के लिए विस्तार योजनाओं पर चर्चा की। एक अन्य दक्षिण कोरियाई फर्म एलएक्स इंटरनेशनल ने राज्य के माइनिंग सेक्टर में काम करने की इच्छा जताई, खास कर लाइमस्टोन (स्टील ग्रेड), सिलिका, जिप्सम, लिग्नाइट, रेयर अर्थ मिनरल्स और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में वह काम करना चाहती है। एक अन्य प्रमुख दक्षिण कोरियाई फर्म ह्योसंग कॉरपोरेशन भारत में स्थानीय स्तर पर कार्बन फाइबर उत्पादन करने पर विचार कर रही है।

स्टोन इंडस्ट्री पर राउण्ड टेबल चर्चा

राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने कोरियन स्टोन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक राउण्डटेबल डिस्कशन में भी हिस्सा लिया। इसमें तकनीकी सहयोग, राजस्थान में उत्पादित स्टोन्स की खरीद एवं वितरण और प्रदेश से निर्यात बढ़ाने पर चर्चा की गई। कोरियन स्टोन एसोसिएशन और राज्य सरकार के उपक्रम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गयी। कोरिया स्टोन एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल अक्टूबर में राजस्थान का दौरा करेगा। इस चर्चा के दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें फरवरी 2026 में जयपुर में आयोजित होने वाले इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में भी आमंत्रित किया।

सियोल तकनीकी हाई स्कूल का दौरा

मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने सियोल तकनीकी हाई स्कूल का भी दौरा किया और राजस्थान के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दक्षिण कोरिया और राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने छात्रों के बीच नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली उल्लेखनीय पहलों, स्कूल के एडवांस्ड टेक्निकल सेंटर को भी देखा, छात्रों के साथ बातचीत की और कक्षाओं में सिखाई जा रही अत्यधिक उन्नत AI तकनीक का अनुभव किया। ■

हमारी सरकार राज्य में शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार पर बहुत जोर दे रही है। युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के व्यावहारिक क्रियान्वयन से प्राप्त ज्ञान युवाओं को सैद्धांतिक समझ के अलावा गतिशील और व्यावहारिक बनाता है। मैं सियोल तकनीकी हाई स्कूल के इस प्रतिष्ठित संस्थान को राजस्थान आने और राज्य में एक संस्थान स्थापित करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री

'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024

प्रथम अंतरराष्ट्रीय 'इन्वेस्टर मीट' का तृतीय दिवस : टोक्यो

जापान

11 सितम्बर, 2024

नीमराणा जापानी निवेश क्षेत्र राजस्थान की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण

'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के दक्षिण कोरिया रोड शो के सफल आयोजन के बाद, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 11 सितम्बर को जापान की राजधानी टोक्यो में निवेशकों की बैठक (रोड–शो) में भाग लिया।

इस रोड शो को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राजस्थान में निवेश करने और मौजूदा संबंधों को मजबूत करने के लिए जापानी निवेशक समुदाय और उद्यमियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, "जापानी निवेशकों के लिए उपयुक्त व्यापारिक वातावरण प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता नीमराणा स्थित जापानी निवेश क्षेत्र की सफलता से स्पष्ट है, जहां अब तक 48 से अधिक जापानी कंपनियों ने लगभग 8.34 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और 26,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। यह 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक जीवंत उदाहरण है। इसकी सफलता से प्रेरित होकर, हमारी सरकार राज्य में दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र भी विकसित कर रही है। जापान के साथ हम न केवल निवेश, बल्कि एक स्थायी और दीर्घकालिक साझेदारी करना चाहते हैं।"

प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में जापान की कुछ चुनी हुई कंपनियों के सीईओ और बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात की और उन्हें राजस्थान में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। इन जापानी बिजनेस लीडर्स में काई ग्रुप के उपाध्यक्ष श्री ताकेशी मिजुतानी, यामाशिता रबर के अध्यक्ष और सीईओ श्री डेसुके यामाशिता, ईएंडएच प्रिसिजन इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ श्री यासुहिरो हिराओका और ताकाहाटा प्रिसिजन के सीएसओ श्री नोबुयुकी अको शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने जेट्रो, काई ग्रुप, निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग, हिताची, यामाशिता रबर, ईएंडएच प्रिसिजन, ताकाहाटा

> राज्य सरकार निवेशकों की समस्याओं को सुलझाने और कारोबारी माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम जापानी निवेशकों के साथ खास तौर पर कारोबारी रिश्ते मजबूत करना चाहेंगे। राजस्थान में ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन आदि क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया है और राज्य को कारोबार के लिए और अधिक अनुकूल बनाने के लिए कई नई नीतियां भी शुरू करने जा रही है।
>
> **भजनलाल शर्मा**
> मुख्यमंत्री

प्रिसिजन सहित कई जापानी कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। इन बैठकों में मुख्यमंत्री ने राज्य में निवेश करने और जापान और राजस्थान के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रशंसा की।

रोड शो के बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने टोक्यो में रहने वाले अनिवासी राजस्थानी (एनआरआर) समुदाय से भी मुलाकात की। यह वे लोग हैं जो वर्तमान में जापान में रह रहे हैं, लेकिन उनकी जड़ें राजस्थान में हैं। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने अनिवासी राजस्थानियों के समुदाय से जापान में राजस्थान के दूत की भूमिका निभाने और अपने गृह राज्य में निवेश को सुविधाजनक बनाने में मदद करने का आह्वान किया।

> राजस्थान भारत में सबसे अधिक निवेशक-अनुकूल और व्यापार को बढ़ावा देने वाले औद्योगिक राज्यों के रुप में उभर रहा है। लालफीताशाही को शून्य करने और व्यापार के लिए अनुकूल व सरल व्यवस्था बनाने पर राज्य काम कर रहा है। मैं निवेशक समुदाय और व्यापारिक समूहों से 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में शामिल होने का आग्रह करता हूं। यह मंच राज्य में नए व्यापार उद्यमों की खोज के लिए एक आदर्श अवसर प्रदान करेगा।
>
> **सिबी जॉर्ज**, जापान में भारत के राजदूत

बैठक के दौरान उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजिताभ शर्मा ने जापानी निवेशकों के समक्ष राजस्थान में निवेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी और राज्य की नई नीतियों और शासन प्रणाली में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताया। टोक्यो रोड-शो का आयोजन जापान में भारतीय दूतावास और जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जेट्रो) की मदद से किया गया था।

नीमराणा दिवस समारोह मनाया, दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र 'घिलोट' में

जापानी व्यापारिक समुदाय और राजस्थान राज्य के बीच साझेदारी को चिह्नित करते हुए रोड शो में 'नीमराणा दिवस समारोह' भी आयोजित किया गया। नीमराणा राजस्थान के अलवर जिले में एक विशेष जापानी निवेश क्षेत्र है, जहां कई जापानी कंपनियां हैं और यह देश-विशेष निवेश क्षेत्र के एक सफल मॉडल के रूप में उभरा है। इसकी सफलता से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार नीमराणा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर 'घिलोट' में दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र भी स्थापित कर रही है। निवेशकों के साथ हुई इस बैठक में राजस्थान के पर्यटन परिदृश्य को प्रदर्शित करने वाली एक फिल्म भी दिखाई गई और जापान के निवेशकों को राज्य के पर्यटन क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं से अवगत कराया गया। ■

'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024

अंतरराष्ट्रीय 'इन्वेस्टर मीट' का चतुर्थ दिवस

जापान

12 सितम्बर, 2024

मुख्यमंत्री की जापान सरकार के मंत्रियों से मुलाकात

वाफुकु ग्रुप की प्रदेश में अस्पताल और जापानी भाषा का संस्थान स्थापित करने में रुचि

मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने 12 सितम्बर को जापान सरकार के मंत्रियों से बातचीत की और राजस्थान में निवेश को सुविधाजनक बनाने में जापान के निरंतर सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। इनमें अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग के संसदीय उप-मंत्री श्री इशी ताकू और लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और पर्यटन मंत्रालय के संसदीय उप-मंत्री श्री इशीबाशी रिंटारो के साथ हुई बैठकें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें दिसंबर में आयोजित 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

जापानी कंपनियों के साथ व्यावसायिक सहयोग का विश्वास जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एनर्जी स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन, केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्र राज्य सरकार की प्राथमिकता हैं और इनमें निवेश के अनेक अवसर मौजूद हैं।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड, वाफाकू हॉस्पिटल्स एंड होम केयर ग्रुप, तोहो ग्रुप सहित अन्य प्रमुख जापानी फर्मों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की।

होंडा मोटर के साथ हुई बैठक के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने राज्य में दी गई मौजूदा सुविधाओं, अवसरों और राजस्थान सरकार के निरंतर

समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि राजस्थान उनकी दीर्घकालिक और विस्तार योजनाओं में प्रमुख रूप से शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में निवेश के अवसरों और संभावनाओं की चर्चा की और सुझाव दिया कि जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में ईवी इकाई के लिए कंपनी संभावित जगह तलाश सकती है।

इसके अलावा वाफुकु अस्पताल और होम केयर समूह के अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के मुलाकात की। इस बैठक में कंपनी के अधिकारियों ने राजस्थान में एक अस्पताल और जापानी भाषा का संस्थान स्थापित करने में अपनी रुचि जतायी और कहा कि इससे 5-6 सालों में तकरीबन 10,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

जापानी कंपनी तोहो ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निवेश के अवसरों और कारोबार को अनुकूल बनाने के सरकार के प्रयासों के बारे में बात की। इस अवसर पर उन्होंने तोहो ग्रुप को राजस्थान में निवेश करने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया।

इससे पहले, सुबह मुख्यमंत्री और प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। विभिन्न कंपनियों से मुलाकात के बाद इस प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में भारतीय दूतावास के अधिकारियों से भी मुलाकात की। इसके साथ ही राजस्थान सरकार का यह प्रतिनिधिमण्डल 13 सितम्बर को जापानी शहर ओसाका में कई जापानी फर्मों के साथ होने वाली एक और इन्वेस्टर्स मीट के लिए रवाना हुआ। ■

'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024

अंतरराष्ट्रीय 'इन्वेस्टर मीट' का पंचम दिवस : ओसाका

जापान

13 सितम्बर, 2024

जापान के निवेशकों को मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का राजस्थान में निवेश का आमंत्रण 'पधारो म्हारे देस'

अपनी तीन दिवसीय जापान यात्रा के अंतिम दिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ओसाका में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में भाग लिया और जापानी निवेशकों से राजस्थान में अपने मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने और नए उद्यम स्थापित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने दो प्रमुख जापानी कंपनियों - डाइकिन और एनआईडीईसी कॉरपोरेशन - के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की। इन कंपनियों के राज्य के नीमराणा जापानी निवेश जोन में पहले से ही उपक्रम हैं।

ओसाका में निवेशकों की बैठक में राज्य में मौजूद कारोबार की संभावनाओं की बात करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राजस्थान के प्रति विश्वास जताने के लिए जापानी निवेशकों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं जापानी निवेशक समुदाय से राजस्थान में अपना विश्वास बनाए रखने और भारत और जापान के बीच मौजूदा साझेदारी को और मजबूत बनाने का आग्रह करता हूं। राजस्थान में नीमराणा जापानी निवेश क्षेत्र में लगभग 50 जापानी कंपनियों का सफल संचालन राज्य की व्यापार करने में आसानी और व्यापार के माहौल को बेहतर बनाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आने वाले दिनों में हम एमएसएमई नीति, 'एक जिला एक उत्पाद' नीति, डेटा सेंटर नीति जैसी कई नए निवेशक-अनुकूल नीतियों को शुरू करने जा रहे है, ताकि राज्य निवेशकों और व्यवसायों के लिए एक प्रमुख आकर्षक स्थान के रूप में उभर सके।"

ओसाका यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के नीमराणा के जापानी निवेश क्षेत्र में अवस्थित एक प्रमुख कंपनी

डाइकिन इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। डाइकिन इंडस्ट्रीज का मुख्यालय ओसाका में है, जहां इस अवसर पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कम्पनी के बारे में बताया, खासतौर पर राजस्थान में मौजूद उपक्रम के बारे में और राज्य में कंपनी के विस्तार योजनाओं पर चर्चा की। इसके अलावा, इस दौरान मुख्यमंत्री कंपनी के टेक्नीकल इन्नोवेशन सेंटर को देखने भी गए।

ओसाका में इन्वेस्टर्स मीट के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने एक अन्य जापानी कंपनी एनआईडीईसी कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और प्रदेश में सरकार द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण व्यापार-अनुकूल परिवर्तनों के बारे में जानकारी दी। एनआईडीईसी कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने राज्य द्वारा व्यावसायिक माहौल को अच्छा बनाने के लिए उठाए जा रहे प्रभावशाली कदमों की सराहना की और आश्वासन दिया कि कंपनी की दीर्घकालिक योजनाओं में राजस्थान भी शामिल है। ओसाका में अनिवासी राजस्थानी समुदाय (एनआरआर) के लोगों ने भी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

ओसाका निवेशकों का रोड शो ओसाका-कोबे में भारत के महावाणिज्य दूतावास, और जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसके साथ ही, 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 के लिए इन्वेस्टर्स मीट और आउटरीच का पांच दिवसीय दक्षिण कोरिया-जापान चरण 13 सितम्बर को समाप्त हो गया और राजस्थान सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राज्य के लिए रवाना हुआ। ■

जापान में तकनीकी नवाचारों की शुरुआत करने में अप्रवासी राजस्थानी समुदाय की भूमिका प्रशंसनीय है और मैं उनसे जापान और राजस्थान के बीच एक सेतु की भूमिका निभाने का अनुरोध करता हूं। साथ ही जापानी संस्कृति से मिली सीख को राज्य के लोगों से भी साझा करने का आग्रह करता हूं। अप्रवासी राजस्थानी अपनी माटी में भी नए व्यवसाय लगाने का प्रयास करें।

भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री

'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के लिए दक्षिण कोरिया और जापान में इन्वेस्टमेंट मीट सम्पन्न कर सफल विदेश यात्रा से लौटने पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट के बाहर भी विभिन्न स्थानों पर आमजन ने मुख्यमंत्री का ढोल-नगाड़ों के साथ उत्साहपूर्वक स्वागत किया। बुजुर्गों, महिलाओं एवं युवाओं ने विकसित राजस्थान के लिए लगातार किए जा रहे फैसलों एवं प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। ■

RISING RAJASTHAN
9-10-11 DEC 2024 • JAIPUR

कोरिया-जापानी दौरे से लौटकर समिट की तैयारियों की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 9 से 11 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट के लिए समस्त अधिकारियों को टीम भावना के साथ मिलकर काम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन से सामने आया है कि राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है।

अपनी कोरिया और जापान यात्रा से लौटकर अगले ही दिन समीक्षा बैठक लेते हुए उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को निर्देश दिए कि इस समिट के सफल आयोजन के लिए तय समय में सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने दिल्ली में आयोजित होने वाले आगामी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मीट के लिए भी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के लिए दिशा-निर्देश दिए।

विभाग स्तर पर होगा प्री-समिट का आयोजन

मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए विभागीय स्तर पर प्री-समिट का आयोजन कार्ययोजना के साथ किया जाए। उन्होंने पर्यटन, नगरीय विकास एवं आवासन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उद्योग एवं वाणिज्य व रीको, कृषि एवं पशुपालन, शिक्षा, खान एवं पेट्रोलियम, ऊर्जा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को प्री-समिट के जरिये संबंधित क्षेत्र के निवेशकों के साथ बैठक आयोजित कर निवेश आकर्षित करने के निर्देश दिए।

जिला स्तर पर भी होंगे इन्वेस्टर्स मीट

श्री शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान की सफलता में जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स मीट की भूमिका अहम होगी। इसके लिए जिला कलक्टर्स एवं संबंधित विभाग स्थानीय स्तर पर निवेश के इच्छुक उद्यमियों से संवाद स्थापित कर बैठक आयोजित करें, जिससे निवेश धरातल पर मूर्त रूप ले सके और रोजगार के नवीन अवसर सृजित हो सकें।

मुख्यमंत्री ने बैठक में विभिन्न देशों एवं देश के विभिन्न राज्यों में जाकर निवेशकों के साथ बैठक करने वाले अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने राजस्थान फाउंडेशन के तहत प्रवासी राजस्थानियों को भी प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के निर्देश दिए। ■

यूएई और कतर में अन्तरराष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिमण्डल का तीन दिवसीय दौरा

राजस्थान नई नीतियों के साथ नए अवसरों की भूमि

'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए मुम्बई में 30 अगस्त को पहले इन्वेस्टर मीट के बाद मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कोरिया और जापान का सफल दौरा किया जिसमें कई दक्षिण कोरियाई और जापानी कंपनियों और संस्थाओं ने राजस्थान में कारोबार करने में रुचि दिखाई।

इसी कड़ी में राजस्थान में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने 17 सितम्बर को दुबई, 18 सितम्बर को आबूधाबी और 19 सितम्बर को कतर के दोहा में हुए अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो में हिस्सा लिया।

दुबई में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल जायौदी से मुलाकात हुई। यूएई की कई प्रमुख कंपनियों और यूएई-इंडिया बिजनेस काउंसिल के यूएई चैप्टर के सदस्यों के साथ भी उनकी बैठकें हुईं और उन्हें राजस्थान में निवेश हेतु आमंत्रित किया गया।

दुबई इन्वेस्टर मीट के दौरान उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, पेट्रोकेमिकल्स, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य, अक्षय ऊर्जा, एआई, फिल्म निर्माण क्षेत्रों, सोलर और स्टील मैन्यूफैक्चरिंग, स्वास्थ्य सेवा आदि क्षेत्रों से संबंधित कई कंपनियों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। इनमें यूएई-इंडिया बिजनेस काउंसिल के यूएई चैप्टर से जुड़े व्यापारिक समूहों के साथ हुई बैठकें शामिल हैं, जिनमें केफ होल्डिंग्स, डीपी वर्ल्ड, लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स, अमीरात एनबीडी, शराफ ग्रुप, ईएफएस फैसिलिटीज जैसी कंपनियों के अधिकारियों ने भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल ने दुबई केबल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स, ट्रांसवर्ल्ड, टेक्टन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एलएलसी, एबैकस केमी एलएलसी सहित अन्य कंपनियों के अधिकारियों से भी मुलाकात की।

दुबई इन्वेस्टर रोड शो के दौरान एक प्रेजेंटेशन और फिल्म द्वारा निवेशकों को राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित फोकस सेक्टर्स, प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग के बारे में बताया गया।

संयुक्त अरब अमीरात और कतर में होने वाले इन दोनों अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर्स रोड–शो का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से किया गया, जो 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का समिट पार्टनर है। इसके अलावा पीडब्ल्यूसी (PWC) इंडिया इस इन्वेस्टमेंट समिट का नॉलेज पार्टनर है।

आबूधाबी रोड शो में दी निवेश के फोकस सेक्टर की जानकारी

यूएई दौरे के दूसरे दिन प्रतिनिधिमंडल ने 18 सितम्बर को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी का दौरा किया और वहां स्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कई बड़ी इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और पेट्रोकेमिकल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की तथा उन्हें प्रदेश में व्यापार करने के लिए आंमत्रित किया।

इन बैठकों के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान में कारोबारियों के लिए उपलब्ध संभावनाओं और अवसरों और फोकस सेक्टर की जानकारी दी। इनमें अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, ऑटो और ईवी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, माइनिंग, ईएसडीएम, आईटी एवं आईटीईएस शामिल हैं। इन बैठकों के दौरान राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने टाका, ताजीज, एडीआईए, एडीआईसी और मुबाडला के प्रतिनिधियों को दिसम्बर में जयपुर में आयोजित होने वाले 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

प्रतिनिधिमंडल ने आबूधाबी में इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप के सदस्यों, जिनमें से ज्यादातर राजस्थान मूल के थे, उनसे मुलाकात कर राजस्थान में निवेश लाने की संभावना तलाशने का भी आग्रह किया। प्रतिनिधि मण्डल ने एक दिन पूर्व दुबई में रह रहे अप्रवासी राजस्थानी (एनआरआर) समुदाय के साथ भी मुलाकात कर इसके सदस्यों से राजस्थान और संयुक्त अरब अमीरात स्थित व्यापारिक समुदाय के बीच सेतु बनने का आग्रह किया था। अप्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश से जोड़ने के लिए 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के मुख्य आयोजन के दौरान एक विशेष सत्र का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने दिन में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत श्री संजय सुधीर से शिष्टाचार भेंट की और राजस्थान में निवेशकों को लाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।

दोहा में इन्वेस्टर रोड शो

'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संयुक्त अरब अमीरात में अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो के बाद 19 सितम्बर को कतर की राजधानी दोहा में इन्वेस्टर रोड शो का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान सरकार की ओर से उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इस दौरान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री एवं प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने कतर सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी मोहम्मद बिन हसन अल मल्क से मुलाकात की और कतर सरकार के प्रतिनिधियों को दिसंबर में आयोजित 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

कतर दौरे में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी सीडीसी और कतर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधिकारियों से भी मुलाकात की और उन्हें राजस्थान के रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, शिक्षा और कौशल, ऑटो और ईवी, पर्यटन, स्टार्टअप, माइनिंग और ईएसडीएम, आईटी और आईटीईएस जैसे क्षेत्रों के बारे में बताते हुए प्रदेश में निवेश हेतु आमंत्रित किया।

इस प्रतिनिधिमंडल में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. जोगा राम, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव श्री सिद्धार्थ सिहाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन के एडिश्नल कमिश्नर (इन्वेस्टमेंट) श्री सौरभ स्वामी और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। ■

प्रदेश की बेहतरीन भौगोलिक स्थित और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के मध्य राजस्थान व्यापार के लिए सबसे अनुकूल गंतव्यों में से एक के रूप में उभर रहा है। हमने कई सरकारी नीतियों, नियमों और दिशा निर्देशों को सकारात्मक रुप से या तो बदल डाला है या बदलने की दिशा में हैं ताकि राज्य में व्यापार और कारोबार जगत के अनुरूप माहौल बन सके और राज्य में व्यापार करना ज्यादा आसान हो।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री

निवेशकों की हर संभव मदद करेगी राज्य सरकार

रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस अधिकारियों एवं अन्य राज्यों में कार्यरत राजस्थानी मूल के प्रशासनिक अधिकारियों से समिट एवं निवेश पर चर्चा

तीन दशक लम्बे करियर में पहली बार ऐसा मौका-सेवानिवृत अधिकारी

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेन्ट समिट 2024 के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोक सेवक के रूप में अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव से मिले महत्वपूर्ण सुझाव प्रदेश में निवेश को बढ़ाने में निर्णायक साबित होंगे। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने राइजिंग राजस्थान व निवेश संवर्धन के सम्बन्ध में अनुभव एवं सुझाव साझा किए।

इन अधिकारियों का कहना था कि 30-35 वर्ष के लम्बे प्रशासनिक करियर में पहली बार ऐसा मौका आया है जब मुख्यमंत्री स्वयं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ संवाद कर रहे हैं। अधिकारियों में श्री चन्द्रमोहन मीणा, श्री रवि माथुर, श्री पुरूषोत्तम अग्रवाल, श्री ललित के. पंवार, श्री श्रीमत पांडे, श्री श्याम अग्रवाल, श्री दीपक उप्रेती, श्री मुकेश शर्मा, श्री संजय दीक्षित, श्री राजेश्वर सिंह, श्री डी.बी. गुप्ता, श्रीमती वीनू गुप्ता एवं श्री अजीत सिंह शामिल रहे।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों में पदस्थापित राजस्थानी मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्वेस्टमेंट समिट के संबंध में चर्चा की एवं उनके विचार जाने।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले दिन से ही प्रदेश में बिजली, पानी, परिवहन और आधारभूत ढांचे के विकास पर कार्य कर रही है। राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए नए स्थान चिन्हित किए गए हैं। राज्य सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियां बनाने सहित उनको हरसंभव मदद दे रही है। राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से राज्य सरकार राजस्थान को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए एक आकर्षक राज्य बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों, उद्योगपतियों और निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें। श्री शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। विभिन्न राज्यों में पदस्थापित राजस्थानी मूल के प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल होकर अपने अमूल्य सुझाव दें।

अधिकारियों से मिले उपयोगी सुझाव

राजस्थानी मूल के अधिकारियों से बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब सहित विभिन्न राज्यों के कैडर के अधिकारियों से चर्चा की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अपने-अपने राज्यों में निवेश के लिए किए जा रहे नवाचारों की जानकारी देते हुए कई रचनात्मक सुझाव दिए। बैठक में भारत सरकार के सचिव स्तर से अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर तक के अधिकारी भी जुड़े। ■

> विकसित राजस्थान की यात्रा में राजस्थानी मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके अनुभव, सुझाव और संपर्क राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अधिकारियों से प्राप्त सुझावों को राज्य की महत्वपूर्ण नीतियों में शामिल किया जाएगा।
>
> **भजनलाल शर्मा**, मुख्यमंत्री

उप उच्चायुक्त से ब्रिटिश निवेशकों की सहभागिता पर चर्चा

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से 20 सितम्बर को गुजरात-राजस्थान के ब्रिटिश उप उच्चायुक्त श्री स्टीव हिकलिंग ने मुलाकात की। इस दौरान श्री शर्मा ने श्री हिकलिंग से आगामी 9 से 11 दिसंबर तक राजस्थान में आयोजित होने वाले 'राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट' में ब्रिटिश निवेशकों की सहभागिता पर चर्चा की। साथ ही, मुख्यमंत्री ने राजस्थान में निवेश के अवसरों, आर्थिक विकास की संभावनाओं तथा प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों के बारे में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त के साथ जानकारी साझा की। श्री हिकलिंग ने मुख्यमंत्री को सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान को देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश उप उच्चायुक्त को 'राइजिंग राजस्थान किट' भेंट किया।

राजस्थान में उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं - मुख्यमंत्री

जयपुर में हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन

प्रदेश के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाते हुए देश की दिग्गज आईटी, इंजीनियरिंग, एफएमसीजी कंपनी विप्रो ने जयपुर के महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी में उत्तर भारत का पहला विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट स्थापित किया है। इसके उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस हाइड्रोलिक प्लांट से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा यह राज्य की आर्थिक प्रगति में भी सहायक होगा।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने वाले 'राइजिंग राजस्थान' इन्वेस्टमेंट समिट में निवेशकों को आमंत्रित किया। उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर उद्योगपतियों को निवेश संबंधी सभी कार्य एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेंगे।

औद्योगिक विकास से ही आर्थिक उन्नति संभव

श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में नई औद्योगिक नीति-2024, एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति, राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रॉडक्ट पॉलिसी, राजस्थान वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी जैसी विभिन्न नई नीतियों से निर्यात, लॉजिस्टिक ईको सिस्टम बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में औद्योगिक गति देने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी पांच वर्ष में 53 हजार किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण जैसे अहम निर्णयों से उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी।

बिजली-पानी की उपलब्धता पर काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में पानी तथा बिजली की उपलब्धता के लिए निरंतर निर्णय किए जा रहे हैं। जहां बिजली क्षेत्र में 2 लाख 24 हजार करोड़ के एमओयू किए गए, वहीं पानी के लिए पीकेसी-ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसे निर्णय किए गए, जिससे उद्योगों को उनकी मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में बिजली तथा पानी मिल सके।

अजीम प्रेमजी का जताया आभार

मुख्यमंत्री ने अजीम प्रेमजी का जयपुर में विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट की शुरुआत करने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि अजीम प्रेमजी ने विप्रो का 53 वर्ष तक नेतृत्व किया है तभी विप्रो आज इस मुकाम तक पहुंची है। एक कॉर्पोरेट समूह के रूप में विप्रो की देश-दुनिया में प्रतिष्ठा है। आईटी, इंजीनियरिंग, एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों में यह दिग्गज कंपनी मानी जाती है। साथ ही, प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतरीन काम कर रहा है। ■

हाइड्रोलिक सिलेंडर का आज कन्स्ट्रक्शन, अर्थमूविंग, यूटिलिटी एवं लिफ्टिंग, कृषि, वानिकी, खनन जैसे अनेक क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। ऐसे में देश-विदेश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह संयंत्र उपयोगी साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि इस संयंत्र का आगे विस्तार भी किया जाएगा। उद्योपति प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश करें। सरकार बिजली, पानी, जमीन सहित हर क्षेत्र में उनकी मदद करेगी, जिससे विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि हो सके।

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

हमें राजस्थान हाइड्रोलिक प्लांट की स्थापना के लिए उत्तर भारत में सर्वाधिक उपयुक्त जगह लगी तथा श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने हमें पूरा सहयोग दिया। सरकार द्वारा समयबद्ध सुविधाएं उपलब्ध होने से कम समय में ही यह प्लांट बनकर तैयार हो गया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तहत राजस्थान में शिक्षा गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं तथा आगे भी यह कार्य निरंतर जारी रहेंगे।

अजीम प्रेमजी, चेयरमैन, विप्रो

अग्रणी राजस्थान

को समर्पित 300 दिन

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के कार्यकाल के करीब 300 दिन गुजर चुके हैं। इन बीते दिनों में लोककल्याण को समर्पित राज्य सरकार के निर्णयों से प्रदेश में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी, शेखावाटी जल समझौते जैसे कई निर्णय दशकों से लम्बित थे तो कई नवाचार ऐसे हैं जिन्हें 'आउट ऑफ द बॉक्स' चिंतन कहा जा सकता है, जैसे 'ग्रीन बजट की अवधारणा'। राज्य सरकार ने हर वर्ग और लगभग हर क्षेत्र के कल्याण को अपने 'निर्णय विजन' में रखा है। विकास के प्रतिमान पर प्रदेश पहली बार एक सूत्र में जुड़ा नजर आता है। किसान, महिला, मजदूर, युवा, राज्य कर्मी, उद्योग जगत सभी इस विकास यात्रा में शामिल हैं और यह तो बस अभी शुरुआत है। प्रस्तुत है बीते 300 दिनों में राज्य सरकार के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की झलक.....

- गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेण्डर, जिसमें एनएफएसए लाभार्थियों को भी शामिल कर लिया गया है।
- जयपुर से अयोध्या के लिए विशेष विमान सेवा, बस और रेल सेवा।
- हजारों वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा।
- संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना (एकीकृत ईआरसीपी) प्रारम्भ।
- ताजेवाला हेड से शेखावाटी में यमुना जल का मामला सुलझाया, त्रिपक्षीय एमओयू।
- देवास परियोजना का तृतीय एवं चतुर्थ चरण।
- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0।
- ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये निवेश के एमओयू।
- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में घरेलू संयंत्रों पर 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 8 हजार रुपये, 55 लाख किसानों को लाभ।
- गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस।
- 2 हजार करोड़ की लागत से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन की शुरुआत।
- 33 लाख किसानों को बीज के निःशुल्क मिनिकिट।
- अन्नपूर्णा रसोई योजना प्रारम्भ, अनुदान और भोजन की मात्रा में बढ़ोतरी, श्री अन्न शामिल।
- भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव एवं डीजीपी के स्तर से।
- एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन।
- राज्य में कार्यवाही हेतु सीबीआई को अनुमति की बाध्यता खत्म।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवक-युवतियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण।
- प्रदेश के सभी पुलिस थानों में महिला डेस्क एवं प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन।
- लाडली सुरक्षा योजना में अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में सीसीटीवी कैमरे।
- जन्म से ही आर्थिक सम्बल देने के लिए बालिकाओं को एक लाख रुपए का सेविंग बॉण्ड।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि।
- गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए देय राशि 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये।

- प्रदेश में 11.24 लाख महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 3 साल में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य।
- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, परित्यक्ता, विशेष योग्यजन पेंशन, लघु, सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन बढ़ाकर 1150 रुपये प्रतिमाह।
- अवैध खनन के विरुद्ध विशेष अभियान।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 75 हजार स्वास्थ्य मेले।
- कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी डे-केयर पैकेज।
- सड़क दुर्घटनाओं में जीवन रक्षा के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस।
- मिलावट के खिलाफ प्रदेशभर में व्यापक अभियान।
- कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 ये 12 तक की छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें तथा युनिफॉर्म के लिए प्रति विद्यार्थी 1 हजार रुपए की सहायता।
- अल्प आय वर्ग, लघु/सीमान्त/ बंटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिक परिवार के विद्यार्थियों को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा।
- करीब 400 पीएमश्री विद्यालयों का उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकास।
- किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना।
- 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना।
- रोडवेज बसों के किराये में 60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को 50 प्रतिशत छूट।
- मीसा, डीआरआई बंदियों के लिए लोकतंत्र सम्मान पेंशन योजना बहाल।
- पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में कमी के लिए वैट में 2 प्रतिशत की कटौती।
- पीकेसी-ईआरसीपी के प्रथम चरण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर कार्य आदेश जारी।
- पेपर-लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम, संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध एसआईटी का गठन। साथ ही कार्रवाई करते हुए 170 से अधिक गिरफ्तारियां।
- 'जल जीवन मिशन' योजना में इस वर्ष 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल।
- करीब 20 हजार 370 करोड़ रुपये लागत से 6 वृहद पेयजल परियोजनाएं।
- 183 शहरों, कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु लगभग 5 हजार 180 करोड़ रुपये के कार्य।
- शहरी जल स्रोत जीर्णोद्धार के 32 कार्य 127 करोड़ रुपये की लागत।
- अजमेर शहर को पेयजल के लिए सर्विस रिजर्वायर निर्माण।
- नसीराबाद से नौसरघाटी, कोटड़ा क्षेत्र तक पाइपलाइन का कार्य।
- आवश्यकतानुसार विधानसभा क्षेत्रों में 20-20 हैण्डपम्प एवं 10-10 ट्यूबवैल का निर्माण।
- नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर सीईटीपी एवं एसटीपी निर्माण।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 33 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य।
- प्रदेश में पेयजल सुविधा हेतु लगभग 540 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य करवाये जाएंगे।
- विभागीय वाटर टेस्टिंग लैब्स को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता, उन्हें ऑनलाइन करना।
- आगामी 10 वर्षों हेतु आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की कार्य योजना तैयार।
- वर्ष 2031-32 तक परम्परागत स्रोतों से 20 हजार 500 तथा अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 33 हजार 600 मेगावाट क्षमता का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु कार्य प्रारम्भ।
- आरवीयूएनएल एवं केन्द्रीय उपक्रमों के मध्य ज्वाइंट वेंचर अण्डरटेकिंग बनाकर 3 हजार 325 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित परियोजनायें स्थापित करने हेतु एमओयू।
- वर्तमान में अनुबंधित 9 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा के अतिरिक्त 13 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए टेरिफ बेस्ड टैण्डर प्रक्रिया से 8 हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के साथ ही 'कुसुम योजना' के तहत 5 हजार मेगावाट का कार्य प्रगतिरत।
- कुसुम योजना के अन्तर्गत 3 हजार 500 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लिए लैटर्स ऑफ इन्टेन्ट जारी।
- वर्ष 2031-32 तक की ऊर्जा मांग की पूर्ति हेतु 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये की लागत के कार्य।
- अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को गति देने के लिए आवश्यक लैण्ड पॉलिसी।

- अब निजी क्षेत्र के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को भी गति देते हुए 50 हजार मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में सोलर पार्क विकसित किये जाने का कार्य।
- राज्य में ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित किये जाने हेतु नीति। पम्प स्टोरेज का भी समावेश।
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 'आदर्श सौर ग्राम'। प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेन्द्रीकृत सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना हेतु 40 प्रतिशत अनुदान।
- सभी राजकीय कार्यालयों को राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन के माध्यम से सौर ऊर्जा से जोड़ना।
- बिजली से वंचित 2 लाख 8 हजार से अधिक घरों को घरेलू बिजली कनेक्शन।
- विद्युत छीजत रोकने तथा आगजन की सुविधा के लिए समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर्स।
- एनर्जी ऑडिट के लिए 3 वर्षों में 4 लाख 34 हजार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स पर चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर्स।
- विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमता के जीएसएस की स्थापना।
- जैसलमेर के पोकरण में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन।
- SCLL और GAIL से MoUs करते हुए 4 हजार 100 मेगावाट क्षमता का सृजन।
- केन्द्र सरकार के सहयोग से कृषकों के खेत पर कुसुम परियोजना में हेम मॉडल के माध्यम से एक हजार मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से चरणबद्ध रूप से लगभग 2 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का सृजन।
- निजी क्षेत्र को अतिरिक्त प्रोत्साहन, कैप्टिव पावर उत्पादन सीमा 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत।
- प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 करोड़ रुपये की सड़कों व 3 करोड़ रुपये के अन्य आधारभूत संरचना कार्य।
- इस सरकार के कार्यकाल में 53 हजार किमी सड़क नेटवर्क पर 60 हजार करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- 9 हजार करोड़ रुपये की लागत से राज्य उच्चमार्ग सड़कों के साथ बाइपास सड़कों, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड्स, आरओबी, आरयूबी एवं हाई लेवल ब्रिजेज आदि का निर्माण तथा रिपेयर व उन्नयन।
- प्रदेश में प्रथम बार 2 हजार 750 किलोमीटर से अधिक की लम्बाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे।
- बिपरजॉय तूफान, अतिवृष्टि एवं समय पर रखरखाव की कमी के कारण क्षतिग्रस्त एक हजार 343 सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत व जीर्णोद्धार करने के लिए 2 वर्षों में 644 करोड़ रुपये का व्यय।
- उपखण्ड, पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से 2 लेन चौड़ी सड़क से जोड़ने का निर्णय। चरणबद्ध रूप से इस पर लगभग 306 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
- शहरी क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत एवं उन्नयन 500 करोड़ रुपये की लागत से।
- जनगणना 2011 के आधार पर निर्धारित आबादी के एक हजार से अधिक राजस्व गांवों को डामर सड़क से कनेक्टिविटी।
- सड़कों के विस्तार-सुदृढ़ीकरण हेतु 2 हजार करोड़ रुपये से विभिन्न सड़क निर्माण कार्य।
- बाड़मेर में अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित मुख्य सड़कों से वंचित सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 34 सैनिक चौकियों तक सुगम पहुंच बनाने एवं सैनिकों की सुविधा के लिए चरणबद्ध रूप से सड़कों का निर्माण।
- ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को भी शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधायें उपलब्ध कराने के क्रम में 10 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट 'अटल प्रगति पथ' का निर्माण।
- बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा के उन्नयन के लिए एक हजार ई-बसें।
- पेरि-अर्बन क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से "राजस्थान रीजनल एण्ड अर्बन प्लानिंग बिल-2024"।
- विभिन्न जिलों की समस्याओं के निस्तारण हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान कर 'डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना'।
- प्रदेश में जिला स्तर के एवं अन्य चयनित शहरी निकायों में वाई-फाई अनेबल्ड लाइब्रेरी एण्ड को-वर्किंग स्टेशन्स की स्थापना।
- विभिन्न नगरीय निकायों में बिजली की लाइनों को भूमिगत करने के लिए 150 करोड़ रुपये का एवं चरणबद्ध रूप से प्रत्येक नगरीय निकाय में 65 करोड़ रुपये की लागत से फायर ब्रिगेड।
- ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु 71 नगरीय निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट्स, 86 नगरीय निकायों में मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केन्द्र तथा 131 नगरीय निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण की व्यवस्था।

- कचरा संग्रहण व परिवहन से निस्तारण व्यवस्था हेतु- व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम्स एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस का उपयोग करने के साथ-साथ नगर निगमों में संचालित इंटरमीडिएट ट्रांस्फर स्टेशन्स को मैकेनाइज्ड एवं ऑटोमेटेड कराया जायेगा।
- विभिन्न शहरों में ड्रेनेज, जल संरक्षण, जन सुविधा व सामुदायिक कार्य तथा अल्प आय वर्ग के लिए आवास निर्माण सम्बन्धी कार्य एक हजार 300 करोड़ रुपये की लागत से।
- प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों के बाजारों एव सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं के लिए बायो, पिंक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स। प्रथम चरण में, नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्रों में 67 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स।
- राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 बसें क्रय करने के साथ ही 800 और बसें सर्विस मॉडल पर लिये जाने का निर्णय। इसके अन्तर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जायेंगी।
- प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारम्भ होगी।
- अजमेर, भरतपुर, दूदू, कोटा एवं उदयपुर सहित 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधायुक्त बस पोर्ट्स, स्टैण्ड्स बनाए जाएंगे। साथ ही, विभिन्न बस स्टैण्ड्स, डिपो एवं वर्कशॉप्स की मरम्मत, रखरखाव एवं जन सुविधा के लिए 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- बहरोड़,कामां-डीग, रूपवास-भरतपुर, बायतू-बालोतरा श्रीडूंगरगढ़-बीकानेर, महवा-दौसा, सपोटरा-करौली, मनोहर थाना-झालावाड़, धोद, खण्डेला-सीकर एवं पिंडवाडा-सिरोही में बस स्टैण्ड सम्बन्धी विकास कार्य।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में एक हजार 650 कार्मिकों की भर्ती की जायेगी।
- जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा एवं बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में नगरीय परिवहन के लिए चरणबद्ध रूप से जीसीसी मॉडल आधारित 300 इलेक्ट्रिक बसें क्रय की जायेंगी। साथ ही, ई-बसों के सुगम संचालन हेतु 25 करोड़ रुपये व्यय कर मॉडर्न शेल्टर कम चार्जिंग स्टेशन स्थापना।
- जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का केन्द्र सरकार के साथ ज्वांइट वेंचर।
- पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए बृज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारम्भ।
- डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु इस वर्ष 50-50 करोड़ रुपये।
- प्रदेश के बड़े शहरों के विकास को गति देने हेतु बीकानेर एवं भरतपुर में यूआईटी का उन्नयन कर विकास प्राधिकरण का गठन।
- नगरीय निकायों में जन सुविधा के कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सम्पादित करने हेतु जिला स्तर पर जिला नगरीय आयुक्त की नियुक्ति।
- जयपुर के सौन्दर्यीकरण के साथ ही जल संरक्षण को बढ़ाने हेतु द्रव्यवती नदी के विकास की नवीन योजना।
- दस हजार से अधिक आबादी वाले कस्बों व आस-पास के गांवों को सम्मिलित करते हुए चरणबद्ध रूप से 100 कलस्टरों में फिकल स्लज प्रबन्धन।
- "इंडस्ट्रीयल पॉलिसी-2024" लाई जायेगी।
- थीम आधारित इंडस्ट्रीयल पार्क की स्थापना बनेंगे।
- नवीन "एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी"।
- पृथक "गारमेंट एण्ड अपैरेल पॉलिसी" लायी जाएगी।
- राजस्थान वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टक पॉलिसी बनेगी।
- विश्व के प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से राजस्थान फाउण्डेशन के नये चैप्टर शुरू हांगे।
- बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना।
- प्रदेश में डिफेन्स मेन्यूफैक्चरिंग हब की स्थापना।
- जयपुर में 'अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लीकेशन सेंटर' की स्थापना।
- "डेटा सेंटर पॉलिसी" भी लायी जायेगी।
- "राजस्थान-वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट पॉलिसी-2024" लायी जाएगी।
- जयपुर में पीएम-यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा।
- एमएसएमई पॉलिसी- 2024 बनेगी।
- माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा।
- नवीन रिप्स योजना लायी जायेगी। रिप्स फण्ड गठित होगा।
- एमएसएमई उद्यमियों को कॉमन सैम्पलिंग एवं मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संभाग मुख्यालयों सहित 20 स्थानों पर रीजनल लैबोरेट्रीज स्थापित की जाएंगी।
- युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में अन्तर्गत 6 प्रतिशत ब्याज पुनर्भरण हेतु ऋण की सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये।
- "नवीन पर्यटन नीति" लायी जाएगी।

- विश्वकर्मा योजना के अन्तर्गत 18 ट्रेड्स के दस्तकारों को उपलब्ध 5 प्रतिशत की दर पर ऋण हेतु 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान।
- खुशियारा-बारां व पण्डेर (जहाजपुर)-शाहपुरा में औद्योगिक पार्क एवं अजमेर में IT Park स्थापित किये जांएगे।
- सशुल्क सेम्पलिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बांसवाड़ा, बूंदी, हनुमानगढ़, झालावाड़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनूं, नागौर, राजसमंद, सवाई माधोपुर व सिरोही में एनबीएल प्रमाणित लैब्स की स्थापना।
- राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन, "राजस्थान ट्यूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग फण्ड बनाकर सरकार के इस कार्यकाल में 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य।
- "राजस्थान हेरिटेज कन्जर्वेशन एण्ड डवलपमेंट अथॉरिटी" बनाई जाएगी।
- खाभा फोर्ट परिसर जैसलमेर में फॉसिल पार्क एवं ओपन रॉक्स म्यूजियम बनाये जायेंगे।
- दिल्ली के 'भारत मण्डपम्' की तर्ज पर जयपुर में 'राजस्थान मण्डपम्' बनाया जाएगा।
- लैपर्ड रिजर्व झालाना-जयपुर, जवाई-पाली आदि को भी ईको-ट्यूरिज्म सर्किट का भाग बनाया जाएगा।
- सांभर झील, खींचन कन्जर्वेशन रिजर्व, शेरगढ़ अभयारण्य, मनसा माता कन्जर्वेशन रिजर्व एवं बस्सी अभयारण्य को ईको-ट्यूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जायेगा।
- जोगी महल-सवाई माधोपुर, आमेर-जयगढ़-नाहरगढ़ किला - जयपुर, बिजासन माता (इंदरगढ़)-बूंदी, समई माता-बांसवाड़ा तथा छतरंग मोरी-चित्तौड़गढ़ में रोप-वे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डीपीआर बनायी जाएगी।
- प्रथम चरण में सरिस्का स्थित पांडूपोल और रणथम्भौर में त्रिनेत्र गणेश जी के लिए ईवी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जायेगा।
- खाटूश्यामजी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये व्यय कर कार्य करवाये जाएंगे।
- प्रदेश में विभिन्न त्योहारों जैसे-दीपावली, होली, शिवरात्रि एवं रामनवमी आदि पर लगभग 600 मंदिरों में विशेष साज-सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिन पर 13 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- राज्य में मंदिरों के जीर्णोद्धार व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के विकास कार्य किए जाएंगे।
- जनजाति आस्था केन्द्र सीताबाड़ी-बारां, कमलनाथ महादेव व जावर माता मंदिर-उदयपुर के प्रांगण एवं आसपास के स्थलों का समग्र विकास तथा यात्रियों के लिए सुविधायें विकसित की जायेंगी।
- डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में क्रमशः डूंगर बरंडा व बांसिया चारपोटा जनजातीय नायकों के स्मारकों का एवं उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जायेगा।
- डूंगरपुर में शिल्पग्राम बनाया जायेगा।
- रवीन्द्र रंगमंच, जवाहर कला केन्द्र-जयपुर, लोक कला मण्डल-उदयपुर एवं विभिन्न कला- संगीत-साहित्य-भाषा अकादमियों का उन्नयन होगा।
- राज्य अभिलेखागार-बीकानेर में स्थित लगभग 40 करोड़ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स का चरणबद्ध रूप से डिजिटाइजेशन किया जायेगा।
- यात्री सुविधा के लिए जयपुर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की टर्मिनल कैपिसिटी 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रतिवर्ष की जाएगी।
- जयपुर में नए स्टेट टर्मिनल का निर्माण किया जायेगा।
- औद्योगिक नगरी-कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू किया जायेगा। इस सम्बन्ध में एमओयू किया जा चुका है।
- उदयपुर हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार तथा उत्तरलाई -बाड़मेर हवाई अड्डे पर स्थायी सिविल एन्क्लेव व अप्रोच रोड के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी।
- श्रीगंगानगर एवं झालावाड़ हवाई अड्डों के उन्नयन, रिपेयर एवं रखरखाव के कार्य कराये जायेंगे।
- किशनगढ़-अजमेर तथा हमीरगढ़- भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग।
- विवेकानन्द एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के मोनोग्राफ्स प्रकाशित किये जायेंगे।
- सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धान्त का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को 'हरित-राजस्थान' के रूप में उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की दृष्टि से आगामी वर्ष से राज्य का "ग्रीन बजट" भी प्रस्तुत किया जाएगा।
- राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 2028 तक, वन क्षेत्र में 20 हजार हेक्टेयर की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित।
- इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वृक्षारोपण महाभियान के माध्यम से हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौधे लगाने व पालने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है।
- पौधारोपण के क्रम को सतत रखने हेतु मल्टी-सेक्टोरल प्रोग्राम के रूप में मिशन 'हरयाळो-राजस्थान' प्रारम्भ किया गया है।

- प्रदेश में प्रतिवर्ष आवश्यक लगभग 10 करोड़ पौध तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरियां स्थापित की जाएंगी।
- वर्तमान 540 से अधिक नर्सरियों का संवर्द्धन किया जाएगा एवं निजी क्षेत्र, पंचायत के अधीन नर्सरियों के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की जायेगी।
- हर जिले में आमजन की सहभागिता से एक-एक 'मातृ वन' स्थापित किया जाएगा।
- 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन स्पीशीज' कार्यक्रम लागू कर प्रत्येक जिले के लिए विशेष नस्ल की पौध वहां के पर्यावरण को देखते हुए तैयार की जायेगी।
- पौधों का समुचित पालन कर सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए 2 हजार स्थानीय व्यक्तियों को इन्सेन्टिव के आधार पर 'वन मित्र' लगाया जायेगा तथा प्रत्येक क्षेत्र में इच्छुक रिटायर्ड कर्मचारी को गार्जियन के रूप में जिम्मेदारी दी जायेगी।
- महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण, चरागाह विकास तथा वृक्षारोपण के कार्य एक हजार 650 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर करवाये जायेंगे।
- वन से होने वाले लाभ समस्त प्रदेश के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को विशेषकर प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से "ज्वाइंट फोरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी" को सशक्त करते हुए 'वन-धन कार्यक्रम' को प्राथमिकता दी जायेगी।
- ब्लॉक स्तर तक वन उपज एवं सम्बन्धित उत्पादों के विक्रय के लिए मार्केटिंग हब्स विकसित किये जायेंगे।
- वन विभाग के कार्मिकों, "ज्वाइंट फोरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी" के सदस्यों सहित समस्त स्टेकहोल्डर्स की प्रबन्धकीय योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से झालाना-जयपुर में 40 करोड़ रुपये की लागत से फोरेस्ट एण्ड वाइल्डलाइस ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जायेगी।
- वन संरक्षण के अन्तर्गत नवाचार के रूप में फोरेस्ट कार्बन क्रेडिट्स सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म स्थापित किया जायेगा।
- क्लीन कुकिंग प्रोत्साहन तथा कुकिंग फ्यूल के दबाव को कम करने के उद्देश्य से 50 प्रतिशत अनुदान पर 10 हजार सोलर, इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम वितरित किये जायेंगे।
- शहरों में वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए जयपुर की तर्ज पर अलवर एवं भिवाड़ी में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किये जायेंगे।
- ब्राह्मणी नदी (बेगूं)-चित्तौड़गढ़ के रिवर फ्रंट एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य करवाया जाएगा। साथ ही, अजमेर शहर में पार्क व आदर्शनगर में मातृवन विकसित किये जायेंगे।
- काले हिरणों के संरक्षण हेतु शाहपुरा जिले के आशोप क्षेत्र आखेट निषिद्ध व कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र।
- Rajasthan State Pollution Control Board के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर एवं जोधपुर में एवं बोर्ड में Adjudicating Officers की नियुक्ति।
- 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी भर्तियां हांगी।
- 'युवा नीति-2024' लायी जाएगी।
- सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाएंगे।
- युवाओं को आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस आधारित काउन्सलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अप्रेन्टिसशिप, इन्टर्नशिप प्रोग्राम संचालित किये जाएंगे।
- चयनित युवाओं को देश, विदेश में एक्सपोजर विजिट के अवसर उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- "स्टेट स्किल पॉलिसी" लायी जाएगी। प्रचलित पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक बनाते हुए प्रदेश में 2 वर्षों की अवधि में एक लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग करवायी जायेगी।
- युवाओं को स्टार्टअप्स स्थापित करने एवं 'एम्पलॉयमेंट प्रोवाइडर' भी बनने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए "अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम" चलाया जाएगा।
- चयनित स्टार्टअप्स को "अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम" में आई-स्टार्ट फण्ड के तहत 10 करोड़ रुपये तक की फण्डिंग सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी।
- स्टार्टअप्स को इक्विटी फण्डिंग के द्वारा फाइनेन्शियल सपोर्ट दिये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये से फण्ड ऑफ फण्ड बनाया जाएगा। स्टार्टअप्स को विभिन्न विभागों से सीधे वर्क ऑर्डर दिये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं उन्हें सीधे सब-कॉन्ट्रेक्टिंग के माध्यम से कार्य देने की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।
- जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में "अटल इनोवेशन स्टूडियोज" और एक्सीलेरेटर्स स्थापित किये जा रहे हैं। इनके अन्तर्गत एग्रीकल्चर एक्सीलेरेटर्स मिशन प्रारम्भ होगा। इसी के साथ एपीजीसी-एक्सआर पॉलिसी, "एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक एक्सटेन्डेड रियलिटी" पॉलिसी लाई जाएगी।
- आई-स्टार्ट के अंतर्गत लर्न, अर्न एण्ड प्रोग्रेस(लीप) प्रोग्राम प्रारम्भ किया जाएगा।
- विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में "बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम" चलाया जाएगा।

- नाचना (पोकरण)-जैसलमेर में नवीन आईटीआई तथा बांदीकुई-दौसा, फागी-दूदू, वल्लभनगर-उदयपुर, निवाई-टोंक, मारवाड़ जंक्शन-पाली व गुढ़ामालानी-बाड़मेर में नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों सहित 2 वर्षों में 20 ITIs एवं 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाएंगे।
- प्रदेश में उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण के रूप में भरतपुर, बीकानेर व अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेजों का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आरआईटी) स्थापित किया जाएगा।
- प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 'कुलगुरु' की पदवी प्रदान की जाएगी।
- 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, साथ ही 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन होगा तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ किये जाएंगे।
- राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्रा-छात्राओं को देय मैस भत्ता 2 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। साथ ही, खेलकूद आवासीय विद्यालयों के खिलाड़ियों का मैस भत्ता बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रतिमाह किया।
- राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य तथा जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33 हजार विद्यार्थियों को टेबलेट्स विद 3 ईयर इंटरनेट कनेक्टिविटी निःशुल्क दिये जाएंगे।
- भवन विहीन 20 संस्कृत महाविद्यालयों हेतु भवन निर्माण कराये जायेंगे।
- महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जायेगा।
- रैवासा-सीकर में संचालित आदर्श वेद आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किये जाएंगे।
- 'खेल नीति-2024' लाई जाएगी। राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना करते हुए खेल क्षेत्र के लिए गत वर्ष प्रावधित 475 करोड़ रुपये की बजट राशि को चरणबद्ध रूप से दुगुना किया जाएगा।
- प्रदेश में कोचेज एवं स्पोर्ट स्पेशलिस्ट्स तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी।
- संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज की भी स्थापना 50-50 करोड़ रुपये की राशि से की जाएगी।
- प्रदेश में "वन डिस्ट्रिक्ट- वन स्पोर्ट" योजना लागू करते हुए प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित की जाएगी।
- "मिशन ओलम्पिक" के अन्तर्गत केन्द्र सरकार "टारगेट ओलम्पिक पोडियम (टीओपी)" योजना के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध करायी जाएंगी।
- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अन्तरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग एवं प्रेक्टिस सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर स्थापित किया जायेगा। साथ ही, राज्य स्तर के खिलाड़ियों के लिए फिजिकल रिहेब जयपुर में बनेगा।
- चयनित विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में आवश्यक स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं इक्विपमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए पीटीआई, कोचेज की समुचित व्यवस्था की जायेगी।
- ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने की दृष्टि से ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से ओपन जिम व खेल मैदान बनाये जायेंगे। प्रथम चरण में, 10 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों पर ये सुविधाएं विकसित की जायेंगी।
- खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स के लिए डिजिटल रिपोजिटरी।
- प्रस्तावित खेल नीति के अन्तर्गत पैरा एथलेटिक्स के लिए पृथक से विशेष प्रावधान।
- ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 'खेलो राजस्थान' यूथ गेम्स।
- युवा दिवस (12 जनवरी) पर राज्य युवा महोत्सव आयोजन।
- श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर व बाड़मेर सहित 10 जिलों में नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना।
- बाली-पाली, खींवसर-नागौर तथा लोहावट, बापिनी, देचू-फलौदी में खेल स्टेडियम।
- पॉलिटेक्निक, तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश पर बालिकाओं को योग्यता/मेरिट के आधार पर 500 स्कूटी वितरण।
- अलवर एवं भरतपुर में विज्ञान केन्द्र की स्थापना।
- भरतपुर में डिजिटल प्लेनेटेरियम स्थापित किया जायेगा।
- जयपुर में स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेन्द्र।
- प्रदेश में एनसीसी कैडेट्स की संख्या में लगभग 11 हजार की वृद्धि की गई।

- नागौर, जैसलमेर एवं बांसवाड़ा में एनसीसी कार्यालय की स्थापना।
- हिन्दुस्तान स्काउट्स हेतु नियम बनाते हुए 4 करोड़ रुपये का अनुदान।
- शाहबाद-बारां में सहरिया जनजाति वर्ग हेतु तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी।
- अजमेर जिला मुख्यालय पर एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना।
- कपासन-चित्तौड़गढ़ में इनडोर स्टेडियम बनाया जाएगा।
- स्किल सम्बन्धी पीएम पैकेज में प्रदेश के 2 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को लाभ।
- भर्ती परीक्षाओं के बाद दस्तावेज सत्यापन सम्बन्धित विभाग के स्तर पर।
- विज्ञप्ति उपरान्त भी रिक्तियों की संख्या में 100 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान।
- कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रावधानों में बदलाव, समस्त श्रेणियों के लिए न्यूनतम 40 तथा अनुजा, अजजा के लिए 35 प्रतिशत अंक।
- नियमों में परिवर्तन कर वर्षों से अटकी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती होगी।
- वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में एम्प्लॉय एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 पोर्टल तैयार होगा।
- समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु विद्यालयों में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए व्हील व्हील चेयर की व्यवस्था।
- 10 से अधिक विशेष योग्यजन विद्यार्थियों वाले स्कूल में एक केयर अटेण्डेण्ट।
- एनसीसी कैडेट्स का शिविरों के दौरान मैसिंग भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।
- पूरे बजट का 8.26 प्रतिशत भाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रावधित।
- मां योजना के माध्यम से आमजन को और अधिक राहत देने के लिए शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए नये पीडियाट्रिक पैकेजेज जुड़ेंगे।
- निजी चिकित्सा संस्थानों के वर्तमान एम्पैनलमेंट नॉर्म्स में शिथिलन।
- कतिपय पैकेजेज की दरों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा।
- 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना।
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक 'आयुष्मान मॉडल सीएचसी' की स्थापना।
- 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हैल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन'।
- राजस्थान डिजिटल हैल्थ मिशन। पीएचसी स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण कर ई-हैल्थ रिकॉर्ड बनेगा।
- एक हजार 500 चिकित्सकों तथा 4 हजार नर्सिंग कर्मियों के नये पदों का सृजन किया जायेगा।
- दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए 'मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना'।
- थैलेसीमिया पीड़ित व्यक्तियों के उपचार हेतु हिमोटोलॉजिकल सेंटर की स्थापना।
- थैलेसीमिया मरीजों को बिना रिप्लेसमेंट रक्त संचरण की सुविधा।
- अजमेर, भरतपुर, केलवाड़ा-बारां, उदयपुर की औषधि निर्माण रसायन शालाओं का ऑटोमेशन।
- स्तन कैंसर की जांच हेतु मोबाइल वैन्स की संख्या में बढोतरी। प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय पर उपलब्धता।
- आरयूएचएस का उन्नयन कर राजस्थान इन्सटीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना।
- श्रीगंगानगर व मेडिकल कॉलेज-कोटा में कैंसर मरीजों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक लीनयर एक्सीलेरेटर मशीनें।
- राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 2018 के अन्तर्गत Electropathy Board का गठन।
- निष्क्रिय पड़े ट्रोमा सेंटर्स में से 10 सेंटर्स को आवश्यक उपकरण एवं चिकित्साकर्मी उपलब्ध करवाकर ऑपरेशनल किया जायेगा।
- आरयूएचएस-जयपुर, कोलाना (बांदीकुई)-दौसा, साण्डेराव, देसूरी-पाली व प्रतापगढ़ सहित 11 नये ट्रॉमा सेंटर्स की स्थापना।
- राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के दौरान मानव जीवन बचाने हेतु 25 अतिरिक्त एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज।
- प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
- गुड सेमेरिटन को देय प्रोत्साहन राशि को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया।
- पीएम गतिशक्ति योजना के अंतर्गत जयपुर-दिल्ली एवं जयपुर-भरतपुर राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ ही 4 स्टेट हाईवेज पर इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम।

- अजा, अजजा हेतु प्रावधित एससीएसपी, व टीएसपी फण्ड्स की एक-एक हजार करोड़ रुपये की राशि बढ़ाकर एक हजार 500 करोड़ रुपये।
- बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना प्रारम्भ की जाएगी।
- प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए गोविन्द गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना।
- प्रदेश में शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना।
- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को राहत हेतु 25 हजार रुपये प्रति लाभार्थी अतिरिक्त अनुदान।
- स्थायी आश्रय और आवास से वंचित डीनोटिफाइड ट्राइब्स के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमन्तू आवासीय योजना लागू होगी।
- पाक विस्थापितों को आवास के क्रम में ऐसे परिवारों हेतु भी एक लाख रुपये प्रति परिवार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- आज ई-कॉमर्स तथा ऑनलाइन सेवा प्रदायगी कम्पनियों से प्रति ट्रांजेक्शन सोशल सिक्योरिटी चार्ज लेते हुए 250 करोड़ रुपये की निधि का गठन।
- ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार, बालिकाओं के संबलन तथा परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- एससी, एसटी, ओबीसी, सफाई कर्मचारी, अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांगजन के जरूरतमंद परिवारों को रियायती ऋण के लिए सम्बन्धित निगमों को 100 करोड़ रुपये की सहायता।
- ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले 36 लाख बच्चों को को सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा।
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे।
- प्रत्येक आंगनबाड़ी में शुद्ध पेयजल, बिजली एवं गरम पोषाहार हेतु गैस की व्यवस्था। इस प्रथम चरण में इस वर्ष 2 हजार केन्द्र बनेंगे आदर्श आंगनबाड़ी।
- जनजाति समुदाय के बच्चों हेतु 250 नवीन माँ-बाड़ी केन्द्रों की स्थापना।
- 'लखपति दीदी योजना' के अन्तर्गत इस वर्ष लक्ष्य 5 लाख से बढ़ाकर कर 15 लाख।
- 5 वर्षों में 2 लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन होगा।
- इस वर्ष 25 हजार समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड एवं 15 हजार समूहों को आजीविका संवर्धन राशि।
- इस वर्ष 40 हजार नवीन एसएचजी गठित किये जायेंगे।
- एसएचजी महिलाओं को ऋण रियायती दर-2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर।
- जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल एवं पेइंग गेस्ट सुविधा।
- संभागीय स्तर पर चरणबद्ध रूप से बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किये जायेंगे।
- दिव्यांगजन को 20 हजार रुपये तक के आर्टीफिशियल लिम्बस, इक्विपमेंट।
- इंटलैक्चुअल डिसएबिलिटी वाले दिव्यांगों को विशेष लर्निंग किट्स, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को एआई, एआर आधारित स्मार्ट ग्लासेज, श्रवणबाधित विद्यार्थियों को डिजिटल हियरिंग एड्स।
- 2 हजार युवा दिव्यांगजन को स्कूटी।
- प्रदेश में 50 करोड़ रुपये की राशि से रेयर डिजीज फण्ड बनाया जाएगा।
- मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी पीड़ितों को इलेक्ट्रिकल, पॉवर, व्हील चेयर हेतु एक लाख रुपये की सहायता।
- मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित के साथ सहयोगी को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा।
- जामडोली-जयपुर में दिव्यांगजनों एवं वंचित वर्गों हेतु संचालित परिसर में 'स्वयंसिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'।
- वृद्ध, असहाय व्यक्तियों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास हेतु संभाग स्तर पर 'स्वयंसिद्धा आश्रम'।
- स्वतंत्रता सेनानियों को देय सम्मान पेंशन राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर अब 60 हजार रुपये प्रतिमाह।
- द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों की पेंशन राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह।
- प्रदेश के 88 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के बैंक खातों में 1 हजार 37 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एक साथ हस्तांतरित।

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में राशि 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपये की गई।
- 'प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना' के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को देय राशि 6 हजार 500 रुपये बढ़ाकर 10 हजार रुपये।
- राजीविका संचालित संकुल स्तरीय संगठनों के कार्यालय भवनों का निर्माण, मरम्मत एवं नवीनीकरण विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं राज्य वित्त आयोग के माध्यम से।
- समस्त पुराने तथा नये खुदने वाले बोरवैल की एन्ट्री, ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य प्रत्येक बोरवैल के लिए जिम्मेदारी नियत।
- सफाई कर्मचारियों हेतु आरजीएचएस में लंग्स, किडनी एवं स्किन आदि से सम्बन्धित बीमारियों के विशेष पैकेज निःशुल्क।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला, बीपीएल श्रेणी के साथ ही सभी एनएफएसए लाभान्वितों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेण्डर की उपलब्धता।
- पीएमआवास योजना 2.0 के अन्तर्गत प्रदेश के 2 लाख से अधिक अल्प आय एवं मध्यमवर्ग के शहरी परिवारों को चरणबद्ध रूप से लाभ।
- अधिसूचित कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारों के लिए आश्रय योजना।
- भरतपुर में इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर के रूप में कर्मशिला भवन का निर्माण।
- समस्त जिला मुख्यालयों के साथ अन्य प्रमुख स्थानों पर हैलिपेड्स का निर्माण।
- प्रदेश के छोटे नगरीय निकायों में भी समस्त आवश्यक जन सुविधायें उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इनका वित्तीय सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
- नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के गठन तथा परिसीमन सम्बन्धी अभिशंसा हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन।
- सिंगल विन्डो-सेम डे सर्विस डिलीवरी में विभिन्न विभागों की 25 सेवायें 24 घंटों में प्रदान की जाएंगी।
- देश का प्रथम डेटा एक्सचेंज- राजडैक्स बनाया जाएगा।
- डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर-जोधपुर का उन्नयन।
- नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश के लिए फोर्स का गठन।
- पुलिस में 5 हजार 500 नये पदों का सृजन।
- राजस्थान सशस्त्र बल के अन्तर्गत-पद्मिनी, कालीबाई व अमृतादेवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना।
- निर्भया स्क्वॉयड का सुदृढ़ीकरण, विस्तार, 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन।
- जयपुर, जोधपुर व कोटा जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों के साथ एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में अतिरिक्त एक हजार 500 पुलिस कर्मी, ट्रैफिक वॉलिंटियर्स।
- पुलिस हेतु संचार व्यवस्था, तकनीकी उपकरण, आर्म्स-एम्यूनिशन्स, 750 मोटरसाइकिल एवं 500 हल्के वाहन।
- 1 जुलाई, 2024 से लागू नये क्रिमिनल लॉज के प्रावधानों की पूर्ति के लिए आवश्यक आईटी इक्विपमेंट्स।
- कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में रसायन खण्ड स्थापित किये जाएंगे।
- राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मॉर्डनाइजेशन सिस्टम (आरआरसीएमएस) लागू किया जायेगा।
- भूमि सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन, नामान्तरण, गैर-खातेदारी से खातेदारी, भूमि की लीज आदि नामान्तरण के ऑटो, डीम्ड निस्तारण हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
- पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र का अपग्रेडेशन, विस्तार कर राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना।
- अजमेर, जयपुर स्थित राजस्व मंडल एवं कर बोर्ड का एकीकरण किया जाएगा।
- राज्य स्तरीय, 100 seater अभय कमांड सेंटर की स्थापना, 500 अतिरिक्त सेन्ट्रल मोबाइल दल।
- डीजी पुलिस एवं सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को देय गुप्त सुरक्षा निधि की राशि दोगुनी।
- तिजारा-खैरथल में बॉर्डर होमगार्ड्स एक कम्पनी की तैनाती।
- प्रदेश में अग्निवीर युवाओं को पुलिस, आरएसी, जेलप्रहरी, वनरक्षक में नियुक्ति का प्रावधान।
- जमाबंदी में भूमि धारक का आधार एवं खसरों हेतु भू-आधार का अंकन, तथा ग्रामीण, शहरी क्षेत्र में नक्शों को जीआईएस आधारित किया जाएगा।
- नियमों का सरलीकरण करते हुए डीड राइटर्स की संख्या दोगुनी की जाएगी।
- बाट-माप सम्बन्धी व्यवस्था सुदृढ़ीकरण, नवीन आईटी प्लेट फार्म, स्थापना तथा मोबाइल एप सुविधा।

राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि-2008 बहाल

- कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण की वेतन सुधार, वेतन विसंगति सम्बन्धी शेष सिफारिशें लागू की जाएंगी।
- राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स, 2022 अन्तर्गत सृजित पदों के नियमित पदों में परिवर्तन पर उनमें नियुक्ति हेतु अनुभव में वर्ष 2024-25 में 2 वर्ष की छूट।
- 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता।
- पत्रकार साथियों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना।
- बार कौंसिल को एकबारीय सहायता के रूप में 7 करोड़ 50 लाख रुपये प्रदत्त किये जाएंगे।
- राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों हेतु वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की प्रतिवर्ष दो तिथियाँ-01 जुलाई एवं 01 जनवरी निर्धारित।
- राज्य के विशेष योग्यजन श्रेणी कर्मचारियों को एक हजार 200 रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया जाएगा।
- भविष्य में प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ 1 जुलाई से।
- आरजीएचएस अन्तर्गत मेडिकल लाभ की सुविधा हेतु महिला एवं पुरुष कार्मिकों को अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक का विकल्प चुने जाने का प्रावधान।
- पेंशनर्स की आउटडोर चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष।
- 1 अप्रेल, 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन।
- ग्रेच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये।
- स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष निर्धारित।
- उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु बिशनसिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार प्रारम्भ किये जायेंगे।
- अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु पृथक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान जर्नलिस्ट हैल्थ स्कीम।
- सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कौशल पर आधारित 'नव-प्रसारक' नीति लायी जाएगी।
- सरकारी कार्मिक की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य के नहीं होने पर स्थायी रूप से स्पेशियली एबल्ड बच्चे और बच्चों, आश्रित माता-पिता और स्पेशियली एबल्ड भाई-बहन के नाम पीपीओ।
- राजकीय उपक्रमों के आरजीएचएस कार्ड धारक कार्मिकों एवं पेंशनरों की आउटडोर चिकित्सा सुविधा व्यय की प्रतिवर्ष सीमा 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये।
- इन उपक्रमों के आरजीएचएस कार्ड धारक पेंशनरों की मृत्यु पर पात्र आश्रितों को आरजीएचएस सुविधा।
- वृद्ध पेंशनर्स को आरजीएचएस के अन्तर्गत विटामिन, मिनरल्स एवं एन्टी ऑक्सीडेंट्स अनुमत।
- राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारम्भ किया जाएगा।
- प्रदेश के 21 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख (प्रदेश की 40 प्रतिशत) जनसंख्या को पेयजल तथा 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए (ईआरसीपी परियोजना ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट) पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना को त्वरित गति से धरातल पर उतारने के लिए प्रथम चरण में रामगढ़ व महलपुर बैराज-बारां, नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध एवं ईसरदा बांध भरने हेतु आवश्यक कार्यों की 9 हजार 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति एवं वर्क ऑर्डर भी जारी किये जा चुके हैं।
- ईआरसीपी परियोजना के अन्तर्गत 5 महत्वपूर्ण लिंक व चम्बल बेसिन के कार्यों चरणबद्ध रूप से।
- दीर्घगामी योजना बनाकर "रन ऑफ वाटर ग्रिड" स्थापित की जाएंगी।
- शेखावाटी में वर्ष पर्यन्त जल के लिए त्रिपक्षीय यमुना जल समझौता।
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में जीर्णोद्धार एवं सिंचाई संबंधी विभिन्न कार्य।

- नहरी क्षेत्रों में डिग्गी निर्माण हेतु किसानों को अनुदान।
- कृषि कार्य के लिए 31 मार्च, 2024 तक लम्बित एक लाख 45 हजार विद्युत कनेक्शन इसी वर्ष।
- कृषि कनेक्शनों हेतु स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू की जायेगी।
- किसानों को दिन के समय सिंचाई हेतु बिजली दिये जाने का कार्य 2027 तक पूर्ण।
- नदियों के किनारे भूमि कटाव को रोकने हेतु अटरू-बारां सहित 5 स्थानों पर जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण के माध्यम से।
- कृषकों को सौर ऊर्जा के साथ drip/sprinkler irrigation सुविधा, इस वर्ष एक लाख अतिरिक्त किसानों को लाभ, 2 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित।
- राजस्थान कृषि विकास योजना, राजस्थान एग्रीकल्चर एण्ड हॉर्टिकल्चर मिशन का गठन।
- कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अनुदान। इस वर्ष एक हजार कस्टम हायरिंग सेंटर्स।
- 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में दो-दो क्लस्टर्स का विकास।
- ऑर्गेनिक एण्ड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड का गठन किया जायेगा।
- जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु जिलों में यूनिट्स एवं लैब्स की स्थापना।
- ब्लॉक स्तर पर 50-50 कृषकों को गौवंश से जैविक खाद उत्पादन हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना।
- प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी योजना में नेनो यूनिया एवं पेस्टीसाइड्स का छिड़काव करने पर 2 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी।
- समस्त जिला मुख्यालयों पर 2 वर्षों में एग्री क्लिनिक की स्थापना।
- प्रथम चरण में 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों तथा साथ ही 5 हजार युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।
- वर्तमान संचालित नौ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की संख्या चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 18 की जायेगी।
- एग्री-स्टेक के माध्यम से किसानों को स्वतः फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।
- 20 हजार किसानों को भूमि सुधार हेतु निःशुल्क जिप्सम उपलब्ध करवाया जाएगा।
- सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर टिश्यू कल्चर एवं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एन्टरप्रोन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट की स्थापना।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में भूमि के उपयोग हेतु भूमि-रूपान्तरण सम्बन्धी प्रावधान।
- काश्तकारों के बकाया सिंचाई शुल्क में मूल राशि एकमुश्त 31 दिसम्बर, 2024 तक जमा करवाने पर 31 मार्च, 2024 तक देय ब्याज माफ।
- रामगढ़, पंचवारा (लालसोट)– दौसा, नसीराबाद – अजमेर, पीपलू – टोंक, बापिणी (लोहावट) – फलौदी, कोटखावदा – जयपुर, परबतसर-डीडवाना कुचामन, सेडवा (चौहटन)-बाड़मेर व भाड़ौती-सवाई माधोपुर में कृषि मण्डी।
- प्रदेश में वनस्पतियों की बेहतर प्रजातियों के विकास हेतु 150 बीज बैंकों की स्थापना।
- नवीन कॉपरेटिव कोड्स लाये जाएंगे।
- इस वर्ष 23 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण, 5 लाख नये किसानों सहित लगभग 35 लाख किसानों को लाभ।
- दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले काश्तकारों को 2 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान।
- दीर्घकालीन सहकारी अकृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान।
- चरणबद्ध रूप से 500 नये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाये जाएंगे।
- 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण
- प्याज भण्डारण संरचना के निर्माण हेतु किसानों को लगभग 22 करोड़ रुपये की सब्सिडी।
- दुधारू पशुओं के साथ-साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना।
- मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन।
- सैक्स सोर्टेड सीमन योजना के तहत अनुदान राशि 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत।
- 125 पशु चिकित्सकों तथा 525 पशुधन सहायकों के नये पदों का सृजन।
- 7 जिलों में राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किये जा रहे हैं। शेष जिलों में भी चरणबद्ध रूप से पशु मेले आयोजित किये जायेंगे।

- ऊँट संरक्षण और विकास मिशन शुरू किया जायेगा।
- नवजात ऊँट के पालन-पोषण की सहायता राशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष।
- सरदारशहर-चूरू, रानीवाड़ा-सांचौर, झालावाड़, भरतपुर, नागौर तथा बीकानेर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स का अपग्रेडेशन व सुदृढ़ीकरण।
- पाली में 30 मीट्रिक टन क्षमता का अत्याधुनिक मिल्क पाउडर प्लांट।
- कोटा में कैटल फीड प्लांट की स्थापना।
- प्रदेश की 100 गौशालाओं को रियायती दरों पर गौ काष्ठ मशीन उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- 2 वर्षों में 2 हजार नये डेयरी बूथ, इस वर्ष शहरी क्षेत्रों में एक हजार सरस मित्र बनाये जाएंगे।
- 2 वर्षों में 1 हजार 500 नई दुग्ध सहकारी समितियां चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाएंगी।
- पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि।
- किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें संगठित सहकारी डेयरी से जोड़ने हेतु 2 हजार दुग्ध संकलन केन्द्र खोले जायेंगे।
- 2 वर्षों में बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना कर 3 लाख लीटर प्रतिदिन प्रशीतलन क्षमता वृद्धि।
- 15 मार्च, 2024 से पेट्रोल एवं डीजल की वैट दर में 2-2 प्रतिशत की कमी की गई। पेट्रोल, डीजल के फ्रेट को रेशनेलाइज कर पेट्रोल की कीमत में अधिकतम 7 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल में अधिकतम 6 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई।
- विविध विलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी की देयता की प्रचलित श्रेणियों को कम करने के साथ ही दरों का रेशनलाइजेशन किया जा रहा है।
- कृषि एवं आवासीय विद्युत कनेक्शन के लिए डिस्कॉम के साथ निष्पादित किये जाने वाले एग्रीमेन्ट, युवाओं द्वारा अप्रेन्टिसशिप संबंधी दस्तावेज, किसानों द्वारा अपनी फसल पर किया जाने वाला बन्धपत्र, शिपिंग से संबंधित विविध विलेख पर भी स्टाम्प ड्यूटी माफ।
- माता-पिता द्वारा पुत्र और पुत्री के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क पर देय पूर्ण छूट पत्नी, पुत्रवधू, पोता, पोती एवं दोहिता, दोहिती के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर भी।
- परिवार के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व के अधीन दो या अधिक गैर-कृषि सम्पत्तियों के एक दूसरे के पक्ष में एक्सचेंज करने पर स्टाम्प ड्यूटी उनमें से अधिकतम मूल्य की सम्पत्ति के मूल्य पर 6 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत।
- सैनिकों के साथ-साथ अर्द्धसैनिक बलों के शहीदों की वीरांगनाओं या उनके पुत्र, पुत्री या माता-पिता को सरकार, निजी संस्था अथवा व्यक्ति विशेष द्वारा निःशुल्क आवास दिये जाने पर स्टाम्प ड्यूटी के साथ ही पंजीयन शुल्क में भी पूर्ण छूट।
- ट्रांसफरेबल डवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) की प्रक्रिया ऑटोमेट करते हुये स्टाम्प ड्यूटी की पूरी छूट तथा इसके विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत।
- आमजन को आसानी से हाउसिंग लोन प्राप्त हो, इसके लिए डेब्ट असाइनमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये। इस प्रकृति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा 25 हजार रुपये।
- स्थानीय निकाय से आवासीय पट्टा जारी हो जाने पर पूर्व के अपंजीकृत दस्तावेजों यथा एग्रीमेंट टू सेल, सोसायटी पट्टा आदि पर स्टाम्प ड्यूटी डीएलसी के 20 प्रतिशत पर की तर्ज पर स्थानीय निकाय का पट्टा नहीं होने पर भी छूट लागू।
- मल्टी-स्टोरी भवनों में 50 लाख रुपये तक के फ्लैट्स की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी 6 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत।
- निर्माणाधीन फ्लैट्स एवं भवनों पर देय जीएसटी राशि पर ली जा रही स्टाम्प ड्यूटी माफ।
- रैफरेंस, अपील से निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी निर्णय के एक माह के अन्दर जमा कराने पर ब्याज माफ।
- दस्तावेज निष्पादन के एक माह के भीतर निरस्तीकरण कराये जाने पर स्टाम्प ड्यूटी एक हजार रुपये।
- रजिस्ट्री में मौका निरीक्षण हेतु सम्बन्धित पटवारी, गिरदावर, ग्राम विकास अधिकारी एवं नगर निकाय अधिकारी भी मौका-निरीक्षक।
- बैंकों एवं वित्तीय कम्पनियों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने सम्बन्धी मूल दस्तावेज के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज स्टाम्प ड्यूटी मुक्त
- कम्पनियों के अमलगेमेशन एवं डीमर्जर पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत।
- राज्य सरकार द्वारा नई राजनिवेश नीति-2024 (रिप्स-2024)।
- ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों में निश्चित समय-अवधि के लिये पीएनजी की वैट दर में 5 प्रतिशत तक कमी।

- निवेशकों द्वारा सिक यूनिट को रिवाइव करने की स्थिति में इन्सेन्टिव्स का प्रावधान।
- रिप्स के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी से छूट हेतु जारी पात्रता प्रमाण-पत्र की अवधि की वैधता अब 2 वर्ष।
- नवीन वैट अधिनियम लाया जाएगा।
- सीएनजी, पीएनजी पर प्रचलित वैट दर 14.5 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत।
- फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एवं एयरक्राफ्ट टाइप ट्रेनिंग आर्गेनाइजेशन के लिये एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर लागू वैट दर को 26 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत।
- कैप्टिव पावर का प्रयोग करने वाले उपक्रम हेतु उपयोगित ऊर्जा से सम्बन्धित ऑग्जीलरी पॉवर पर इलेक्ट्रिकल ड्यूटी समाप्त। बकाया इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का 10 प्रतिशत जमा कराने पर शेष मूल राशि तथा ब्याज, शास्ति माफ।
- ऑनलाइन गेमिंग, ई-कॉमर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिये नवीन इन्टीग्रेटेड प्रणाली का विकास।
- इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये का ई-व्हीकल प्रमोशन फण्ड का गठन।
- स्टेट कैरिज वाहन के अन्य श्रेणी मार्ग पर 300 किलोमीटर से अधिक प्रतिदिन संचालन पर वर्तमान में देय मोटर वाहन कर 504 रुपये से घटाकर 400 रुपये प्रति सीट प्रतिमाह।
- वाहन स्वामित्व हस्तान्तरण में वाहन को भौतिक रूप से प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता समाप्त।
- वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर रिटेन्शन सुविधा वाहन को स्क्रेप कराने पर भी प्रदत्त की जायेगी।
- परिवहन वाहनों की फिटनेस के समय कर-चुकता प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त।
- बाईस (22) सीट से अधिक बैठक क्षमता के यात्रा वाहनों के Special Permit पर मोटर वाहन कर की दर एक समान 600 रुपये तथा पर्यटक यात्रा वाहनों की 875 रुपए।
- नवीन खनिज नीति-2024 लायी जाएगी।
- कतिपय स्थानों पर राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (आरएसएमएमएल) के माध्यम से भी बजरी उत्पादन।
- नवीन एम-सैण्ड पॉलिसी लायी जाएगी।
- बीकानेर में सिरेमिक्स तथा उदयपुर में रेयर अर्थ एलीमेंट्स के लिए सैंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।
- अप्रधान खनिजों के उत्पादन एवं निर्गमन में वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट पद्धति लागू की जायेगी।
- 8 नगरों जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर व पाली में 2 हजार किलोमीटर लम्बाई की गैस पाइपलाइन बिछाकर 1 लाख से अधिक गैस कनेक्शन्स।
- रीको एरिया से 1 किमी की परिधि में लैण्ड कन्वर्जन के लिये रीको की अनापत्ति की आवश्यकता समाप्त।
- 'निजी औद्योगिक पार्क योजना' भी लायी जायेगी।
- लैण्ड एग्रीगेशन एण्ड मॉर्डनाइजेशन पॉलिसी एवं एग्रीगेशन ऑफ प्राइवेट लैण्ड एक्ट लाया जाएगा।
- ट्रांसफर ऑफ इन्डस्ट्रीयल लैण्ड्स वैलिडेशन एक्ट लाया जाएगा।
- पर्यटन एवं एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे प्रोजेक्ट्स, जिनके लिये कृषि भूमि का कन्वर्जन आवश्यक नहीं है, उनके लिये निःशुल्क ऑनलाइन डीम्ड कन्वर्जन ऑर्डर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 15 मीटर की ऊंचाई तक के भवनों के फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु निर्धारित एकमुश्त फीस 50 रुपये प्रति वर्गमीटर से घटाकर 15 रुपये प्रति वर्गमीटर।
- एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी-2024 लायी जाएगी।
- श्रीअन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना करते हुये श्रीअन्न हेतु विशेष प्रावधान किये जायेंगे।
- उद्यमिता एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ ही आमजन को राहत देने के लिये ऊर्जा, उपनिवेशन क्षेत्र संबंधी, वैट, खनन, परिवहन, स्टाम्प एवं आबकारी एमनेस्टी। ■

रुख स्पष्ट है .. 7 करोड़ रुंख प्रत्यक्ष हैं

स्वच्छ विकास, सुरक्षित पर्यावरण के साथ

* रुंख राजस्थानी बोली में वृक्ष को कहा जाता है।

प्राचीन काल से ही हम पेड़, नदी, पहाड़ सभी की पूजा करते हैं। हमारे पूर्वजों ने इसे संस्कृति से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत कार्य किया है। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रकृति की सेवा और मां के प्रति सम्मान का भाव जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को इस अभियान से जुड़ना चाहिए।

भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री

हरयाळो राजस्थान बना जन जन का अभियान

"पेड़ हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन का स्रोत हैं, धरती को उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए पौधरोपण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है..." इस तथ्य को आत्मसात कर राज्य सरकार प्रदेश में पर्यावरण और विकास को साथ लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सक्रियता से प्रदेश ने मानसून सीजन में करोड़ों पौधे लगाकर कीर्तिमान रच दिया है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए वर्ष 2028 तक वन क्षेत्र में 20 हजार हेक्टेयर की वृद्धि करने की घोषणा बजट 2024-25 में की गई है। 'हरयाळो राजस्थान मिशन' के अंतर्गत आगामी पांच साल में 4 हजार करोड़ रुपये की राशि से प्रदेश में 50 नई नर्सरी, प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक-एक मातृवन की स्थापना, खेजड़ली-जोधपुर में 'अमृतादेवी बिश्नोई इंडिजनस प्लांट म्यूजियम' की स्थापना, एक जिला एक नस्ल कार्यक्रम, वन-धन कार्यक्रम चलाए जाने के साथ ही 2 हजार स्थानीय व्यक्तियों को वन मित्र बनाया जाएगा। साथ ही, प्रदेश की सभी विकास परियोजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांत का समावेश करने के लिए आगामी वर्ष से राज्य का 'ग्रीन बजट' प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने माताजी के साथ किया वृक्षारोपण

विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का शुभारंभ किया। राज्य में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपनी माताजी श्रीमती गोमती देवी के साथ बील का पौधा लगाकर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वृक्षारोपण करें तथा पर्यावरण को स्वच्छ और हरा-भरा रखने में अपना योगदान दें।

गौशाला में लगाए गए 7500 से अधिक पौधे

प्रदेश में सघन वृक्षारोपण की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र में 'एक पेड़ गौमाता के नाम' अंतर्गत कदंब और आम का पौधा रोपा। वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अमृता देवी स्मृति पुरस्कार प्रदान किए।

7 करोड़ पौधारोपण का संकल्प पूरा

5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य

राज्य सरकार ने इस वर्ष 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान' प्रारम्भ कर 7 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प पूरा करते हुए आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य के विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों, शहरी निकायों एवं आमजन को पौधे उपलब्ध कराकर तकनीकी सहायता दी जा रही है।

प्रत्येक जिले में होगी 'मातृ वन' की स्थापना

आमजन की सहभागिता से स्मृति वन की तर्ज पर प्रत्येक जिले में 'मातृ वन' की स्थापना की जायेगी। 'मातृ वन' में विभिन्न प्रजातियों जैसे बड़, पीपल, गूलर, पिलखन, नेती पीपल, माखन कटोरी इत्यादि पौधे लगाये जाएंगे। पौधों की देखरेख के लिए 2 हजार 'वन मित्र' लगाए जाएंगे।

हरियाली तीज पर लगाए एक ही दिन में दो करोड़ से अधिक पौधे

हरियाली तीज पर 'एक पेड़ मां के नाम' महा-अभियान राजस्थान के जन-जन का अभियान बन गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दूदू जिला स्थित ग्राम गाडोता के एस.डी.आर.एफ. कैम्पस में पीपल का पौधा लगाकर कार्यक्रम का विधिवत् शुभारम्भ किया। शाम होते-होते अभियान के अंतर्गत 2 करोड़ 7 हजार 485 पौधे लग चुके थे। एक नवाचार के तहत पौधों को 'हरयाळो राजस्थान' ऐप क्यूआर कोड, एपीके, लिंक के माध्यम से जिओ टैग किया गया। विभाग द्वारा जिओ टेगिंग के माध्यम से पौधों को ट्रैक करते हुए पौधों पर नजर रखी जाएगी।

कीर्तिमान

एक घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे रोपे

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान से प्रेरित "मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरयाळो-राजस्थान" के अंतर्गत स्वर्ण नगरी जैसलमेर में जिला प्रशासन, सेना, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), वायु सेना, पंचायती राज संस्थाओं, कृषि विज्ञान केंद्र, वन विभाग तथा आम जनता की सक्रिय भागीदारी से मात्र एक घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे रोपकर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। ■

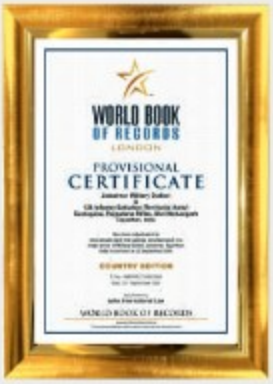

स्वच्छता ही सेवा 2024
17 सितम्बर – 2 अक्टूबर 2024
स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता

स्वच्छता ही सेवा अभियान प्रारम्भ

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 17 सितम्बर को जयपुर में मालवीय नगर पुलिया के पास श्रमदान कर प्रदेश में 'स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की एवं आमजन को स्वच्छता की शपथ दिलाई। अभियान के तहत 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक प्रदेशभर में सामूहिक जन भागीदारी से श्रमदान के माध्यम से गांवों एवं शहरों में सफाई तथा स्वच्छता का कार्य किया जा रहा है। श्री शर्मा ने इस मौके पर नगर निगम के 'रिसाइकिल' एवं 'जयपुर 311' एप का बटन दबाकर शुभारंभ एवं इनके पोस्टर का विमोचन भी किया। 'रिसाइकिल एप के माध्यम से नगर निगम द्वारा सूचना प्राप्त होने पर घर से ही सूखा कचरा श्रेणीवार एकत्रित किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन भुगतान भी किया जाएगा। नगर निगम सबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए शहरवासी जयपुर 311 एप का उपयोग कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधती महिला सफाई मित्र।

सहज–सरल
सुलभ–तत्पर
सब जन – स्वजन

धोरों से उठी 'तरंग' आकाश में बिखरे शौर्य के रंग

भारतीय वायु सेना द्वारा सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यासों में से एक **'तरंग शक्ति-2024'** का आयोजन जोधपुर में 29 अगस्त से 14 सितम्बर तक हुआ। इसमें 27 देशों के 50 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय रक्षा और एयरोस्पेस एक्सपो का उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया।

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2023-25
Registered with Registrar of Newspapers for India under R. No. 56175/1991

Government of Rajasthan

RISING RAJASTHAN
9-10-11 DEC 2024 • JAIPUR
REPLETE • RESPONSIBLE • READY

BHAJANLAL SHARMA
Chief Minister

NARENDRA MODI
Prime Minister

Rajasthan is Rising.
Let's Grow Together!

Rajasthan has set out to realise Hon'ble Prime Minister's vision of Viksit Bharat@2047, with its 'Viksit Rajasthan' Action Plan for becoming a $350 billion economy in next 5 years.

Rising Rajasthan goes beyond being an extraordinary 3-day Investment Summit.

It is the State's socio-economic transformational journey towards inclusive prosperity through... a journey with geographical equity, inclusivity, diversity, sustainability, promotion of MSMEs and job creation as its cornerstones.

The Rising Rajasthan Summit will be preceded by a series of investor Meets in leading business cities across the country and the world, and Sector-focused Conclaves in Jaipur.

- *Rajasthan Opportunity Showcase*
- *Strategic Sector Sessions*
- *Country Sessions*
- *One-on-one Business Meetings*
- *MSME Conclave*
- *Startup Conclave*
- *Non-Resident Rajasthani Summit*

Come, be a part of this Rising!

Department of Industries
Government of Rajasthan

Submit your investment Intent for MoU with Government of Rajasthan

राजस्थान सुजस का यह अंक
https://dipr.rajasthan.gov.in/pages/sm/government-order/attachments/134/85/10/1702
पर देखा जा सकता है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त, सुनील शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक - श्रीमती अलका सक्सेना, मैसर्स रेनबो ऑफसेट प्रिन्टर्स, बी-3, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस' - पृष्ठ संख्या 68, मूल्य 1.00 रुपये • 30,000 प्रतियां